राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 19 नवम्बर 2025 वर्ष-8,अंक-262 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

दिल्ली में सभी जिला अदालतों को मिली बम की धमकी

नई दिल्ली दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट पर रखा गया, जब अधिकारियों को तीस हजारी और साकेत अदालतों को निशाना बनाकर बम की धमकी मिली। इसके बाद द्वारका, साकेत, पटियाला हाउस और रोहिणी अदालत परिसरों में सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि अदालतों को यह धमकी मंगलवार सुबह दो सीआरपीएफ स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद मिली, जिसके बाद आपातकालीन जाँच शुरू हुई, जिन्हें बाद में झूठा अलार्म घोषित कर दिया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, प्रशांत विहार और द्वारका स्थित परिसरों से सुबह करीब 9 बजे धमकियाँ मिलने की सूचना मिली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा टीमों और बम निरोधक दस्तों ने दोनों स्कूलों की गहन जाँच की। इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाद में इस एक अफवाह घोषित कर दिया गया है।

पुलिस और न्याय व्यवस्था की खामियों पर पूर्व सीजेआई ललित ने कहा, समाज में सीता मैया के साथ शूर्पणखा भी

नई दिल्ली पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू लालित ने एक कार्यक्रम में पुलिस और न्याय व्यवस्था की खामियों का खुलाकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के जांच अधिकारियों को न सही पेशेवर उपकरण मिले हैं और न ही जरूरी शिक्षा, जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं। प्रकाश सिंह मामले के फैसले का जिक्र कर पूर्व सीजेआई ने कहा कि जांच विंग को कानून-व्यवस्था शाखा से पूरी तरह अलग करना जरूरी है। जस्टिस ललित ने चिंता जाहिर कि देश में दोषसिद्धि दर कभी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। 5 में से 4 विचाराधीन कैदी अंततः बरी होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम निर्दोष लोगों को हिरासत में लेकर उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे? जस्टिस ललित ने एकम न्याय की अवधारणा को सही बताया। समाज में सीता मैया के साथ-साथ शूर्पणखा भी हैं। इसलिए जांच तंत्र को इस तरह मजबूत करना होगा कि निर्दोषों को अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें। बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता के बयान को सर्वोच्च सम्मान देने की मौजूदा न्यायिक मान्यता सही है। हालांकि, पूर्व सीजेआई ने सुझाव दिया कि अगर आरोप झूठा साबित हो तब झूठी शिकायत करने वाले को अलग से दूसरा मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पूर्व सीजेआई ललित ने प्रेम संबंधों से उत्पन्न होने वाले प्रॉमिस टू मैरी रेप मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, कई बार युवक-युवती खुले मन से रिश्ते में आते हैं। लेकिन बाद में कुछ गलत हो जाता है और एक-दो साल बाद शिकायत आती है कि शादी का झांसा देकर शोषण किया गया।

ध्वजारोहण समारोह: टेंट सिटी में बनेंगे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नगर

अयोध्या प्रभु राम की नगरी अयोध्या एक वैश्विक शहर बन गया है। यहां होने वाले आयोजन भव्यता और दिव्यता को समेटे होते हैं। ऐसे में भीड़ का जुटना स्वाभाविक है। इसी माह 25 तारीख को ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 6 से 8 हजार मेहमान शामिल होंगे। आगंतुकों के लिए एक बड़ी टेंट सिटी बनाई जा रही है। जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के नगर होंगे। अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए मेहमानों का व्यापक पर स्वागत-सत्कार किया जाएगा, जिसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कार सेवक पुरम और तीर्थ क्षेत्र पुरम में भव्य टेंट सिटी तैयार की जा रही है। टेंट सिटी में राम, लक्ष्मण ,भरत और शत्रुघ्न के नाम से नगर बसाए जाएंगे। प्रत्येक नगर में 1000 से अधिक टेंट लगाए जा रहे हैं। जहां करीब 4000 मेहमान के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक इसी प्रकार कार्य सेवक पुरम में भी 1500 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। 20 नवंबर तक दोनों टेंट सिटी का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा ने बताया कि अयोध्या धाम में 5000 से अधिक कमरे तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा ट्रस्ट ने 1600 कमरे आरक्षित किए हैं जिनमें आमंत्रित मेहमानों को ठहराया जाएगा। बड़ी संख्या में आने वाले मेहमानों के लिए छह स्थानों पर भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। सभी मेहमानों का प्रवेश जगदगुरु रामानंदाचार्य द्वारा बिड़ला धर्मशाला के सामने से कराया जाएगा। राम मंदिर परिसर में परकोटे के भीतर आमंत्रित सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था भी अंतिम चरण में है। इसके अलावा अनिल मिश्रा ने बताया कि बाग विदेशी और कार्य सेवक पुरम में ट्रस्ट द्वारा टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश की सीमा पर मारा गया

खूंखार नक्सली हिड़मा, पत्नी समेत 6 नक्सली ढेर

जगदलपुर

सुरक्षाबलों ने खूंखार नक्सली हिड़मा को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की है। मारा गया नक्सली हिड़मा सबसे चर्चित और खतरनाक नक्सली नेताओं में शामिल था। जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश सीमा पर चली मुठभेड़ में 06 नक्सली मारे गए हैं।

इनमें हिड़मा और उसकी पत्नी भी शामिल बताए गए हैं। मौत की अधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। वैसे घटनास्थल से सभी नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए और क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। एर्राबोर थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया था।

इसी अभियान के तहत मंगलवार सुबह से सुरक्षाबल और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षबलों ने घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया। इसके अतिरिक्त सुकमा में दूसरी मुठभेड़ 18 नवंबर की सुबह से जारी है। बताया गया है कि पहली कार्रवाई के साथ ही सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र में भी दूसरे मार्चे पर भी मुठभेड़ चल रही है। इस भिड़ंत के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। दरअसल पुलिस को रात में सूचना मिली थी, कि एर्राबोर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सली एकत्रित हो रहे हैं। इस जानकारी पर डीआरजी जवानों की टीम मौके पर पहुंचीं तो वहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अनेक नक्सली घायल हो गए।

इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही, इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में हुई विभिन्न मुठभेड़ों में 263 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 234 बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें सुकमा सहित सात जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए। वहीं दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में भी हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे।

भारत-डेनमार्क की 8वें दौर की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा

नई दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को भारत-डेनमार्क के बीच आठवीं बैठक हुई। इस दौरान भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने किया, जबकि डेनमार्क पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश नीति राज्य सचिव लोटे माचोन ने किया। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत-डेनमार्क विदेश कार्यालय परामर्श ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा और चर्चा का अवसर प्रदान किया। दोनों पक्षों ने भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत चल रहे सहयोग पर संतोष जताया। दोनों पक्षों ने राजनीतिक जुड़ाव, व्यापार और निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, जल, कृषि और पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विकास और गतिशीलता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वे रक्षा और सुरक्षा, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्कटिक के क्षेत्रों में सहयोग के और अवसर तलाशने पर भी सहमत हुए। डेनमार्क पक्ष ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

डेनमार्क पक्ष ने एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र और

आर्कटिक समेत बहुपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। डेनमार्क साम्राज्य 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य और आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष है। डेनमार्क पक्ष ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया।

दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने बहुपक्षीय जुड़ाव और वैश्विक चुनौतियों पर निरंतर संवाद के महत्व को रेखांकित किया। दोनों पक्ष नियमित परामर्श जारी रखने और कोपेनहेगन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन करने पर सहमत हुए।

भारत पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर, 70त्न लोग कर रहे पानी की कमी का सामना: रिपोर्ट

नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। भारत पर भी इसका बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। 70 प्रतिशत से अधिक भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से भीषण गर्मी, सूखे और पानी की कमी का सामना करने की बात स्वीकार की है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। जलवायु परिवर्तन संचार पर येल कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2025 के बीच 19,000 से अधिक लोगों पर ये सर्वे किया गया। इसके अनुसार

भारत के राज्यों और जिलों में मौसम के अनुभव और जलवायु परिवर्तन की भूमिका के बारे में अलग-अलग धारणाएं रखते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 12 महीनों में 71 भारतीयों ने गंभीर गर्मी की लहरों, 59 ने कृषि कीट और बीमारियों, 59 लोगों ने बिजली कटौती, 53 ने प्रदूषण, 52 सूखा, 52 ने पानी की कमी और 51 ने गंभीर वायु प्रदूषण का अनुभव किया है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता और प्रमुख लेखकों में से एक डॉ. जगदीश ठाकर ने कहा, भारत तेजी से विकास कर रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि विभिन्न राज्यों और जिलों के लोग जलवायु परिवर्तन को कैसे समझते और अनुभव करते हैं। ये मानचित्र स्थानीय और राज्य के नेताओं को ऐसी जलवायु कार्य योजनाएं बनाने में मदद कर सकते हैं, जो लोगों की जीवन वास्तविकताओं को दिखाएं और समाधानों के लिए टिकाऊ जन समर्थन तैयार करें।

पूर्व पीएम हसीना को मौत की सजा, शशि थरुर ने कहा.....यह फैसला मुझे बहुत दुखी करता

नई दिल्ली

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की एक विशेष अदालत ने मौत सजा सुनाई है। यह सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई है। हसीना पर पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है। हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रहीं हैं।

अदालत ने हसीना के साथ उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई है।

यह फैसला अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) ने सुनाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने फैसले को बहुत चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, मैं देश के अंदर या बाहर कहीं भी मौत की सजा में विश्वास नहीं करता। इसलिए यह फैसला मुझे बहुत दुखी करता है।

कांग्रेस नेता थरूर ने सबसे बड़ा सवाल अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने पर उठाया है।

उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति खुद मौजूद न हो, अपना पक्ष न रख सके, खुद की दलील न दे सके और फिर फांसी की सजा सुना दी जाए। यह उचित नहीं लगता।

वहीं 78 साल की शेख हसीना ने फैसले को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने फैसले को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। हसीना ने कहा कि यह सजा एक अवैध अंतरिम सरकार की ओर से गठित फर्जी अदालत ने सुनाई है, इस सरकार को जनता ने नहीं चुना है।

इतना ही नहीं शेख हसीना ने अंतरिम सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अगर इन आरोपों में दम है, तब इन्हें हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) में ले जाओ। वहां सबूतों की असली परख होगी।

पेरिस समझौते के अनुरूप भारत ने सिर्फ 16 महीनों में दो अरब पौधे लगाए गए

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा

नई दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के जलवायु परिवर्तन और भारत की प्रतिबद्धताओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अपनी बात रखी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी30) में भारत के जलवायु लक्ष्यों और विकसित देशों की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। भारत दिसंबर तक 2035 के लिए अपना संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जमा करेगा। ये पेरिस समझौते के तहत देशों की राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं होती हैं, जिनमें उत्सर्जन घटाने और जलवायु प्रभावों के अनुरूप बनने के लक्ष्य शामिल होते हैं। भारत की 2070 तक नेट-जीरो

हासिल करने की यात्रा को हाल ही में शुरू किए गए परमाणु अभियान और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने और तेज किया है। भारत अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी करेगा। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, भारत में सामुदायिक पहल के माध्यम से सिर्फ 16 महीनों में दो अरब पौधे लगाए गए।

केंद्रीय मंत्री यादव ने विकसित देशों से निम्नलिखित अपील की- वे अपने मौजूदा लक्ष्य वर्षों से बहुत पहले नेट-जीरो तक पहुंचें। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और नए, अतिरिक्त व रियायती जलवायु वित्त (ट्रिलियन डॉलर में अनुमानित) का प्रावधान करें। जलवायु लक्ष्यों का क्रियान्वयन पर्याप्त, सुलभ और किफायती होना चाहिए तथा उस पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए। यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक और आसन्न खतरा है, जो अस्थिर विकास और अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ है।

एसआईआर का विरोध: केरल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

कर्मचारियों ने किया बायकॉट का ऐलान

नई दिल्ली

चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के बीएलओ के साथ ही तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनावों को साथ-साथ नहीं कराया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि राज्य में 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनावों होने वाले हैं, जबकि एसआईआर ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। इससे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा कि वे वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इधर, केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनावों के साथ-साथ एसआईआर कराना कठिन है। आयोग ने असम में एसआईआर कराने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, असम में 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे नए वोटरों को शामिल किया जाएगा और पुराने वोटर्स का सत्यापन किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर से अलग है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में स्पेशल रिविजन के लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी, 2026 होगी। यानी इस दिन तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा सकेंगे। घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 27 दिसंबर को होगा।12 राज्यों में छत्तीसगढ़,

गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शौचालय बनाना सिर्फ एक बुनियादी सुविधा न होकर, महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता की लड़ाई है

(लेखक-कांतिलाल मांडोत)

(19 नवम्बर विश्व शौचालय दिवस)

विश्व शौचालय दिवस सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि शौचालय तक पहुँच और स्वच्छता सिर्फ बुनियादी मानवाधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा का मामला है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से महिलाओं का मामला। महिलाओं की स्थिति और शौच के अभाव में चुनौतियाँ बड़ी मुश्किल राहे थी।भारत में पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण, महिलाओं अक्सर खुले में शौच के लिए मजबूर होती थीं। यह सिर्फ स्वास्थ्य-खतरे का मामला नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल था।सुरक्षा और असमर्थता खुले में शौच करने का मतलब होता था दूर-दूर जाना, अक्सर अंधेरे में या असुरक्षित स्थानों पर। महिलाओं के लिए यह खतरा दोगुना था ।उन्हें यौन उत्पीड़न, जान-बचाव की परेशानी और शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, बुज़ुर्ग महिलाएं और किशोर लड़कियों के लिए यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती थी। स्वास्थ्य और स्वच्छताखुले में शौच के कारण कीचड़, कीड़े, बैक्टीरिया और मैल घुला पानी आसपास फैलता था, जिससे डायरिया, गंदे पानी से संक्रामक रोगों का जोखिम बढ़ता था। इस तरह की स्थितियाँ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी असर डालती थीं। गरिमा और सामाजिक दबाव महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए इज्जतघर बहुत मायने रखते हैं। बिना शौचालय के, उन्हें न केवल शारीरिक असुविधा बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती थी। कई जगहों पर महिलाएं इससे जुड़ी सामाजिक बंदिशों और शर्मिंदगी के कारण अपनी ज़रूरतों को छिपाती थीं या जोखिम भरा विकल्प चुनती थीं।सरकार की भूमिका और शौचालय निर्माण की प्रगति स्वच्छ भारत मिशन का दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके दो हिस्से थे। ग्रामीण (एसबीएस-जी) और शहरी (एसबीएस-यू)। इसका प्रमुख लक्ष्य था ओपन डेफेक्शन फ्री (ओडीएफ) भारत बनाना।सरकार ने अपनी नीति में यह माना कि सिर्फ शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है उन्हें बनाना तो पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उपयोग, रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन बेहद ज़रूरी हैं।निर्मित शौचालयों की संख्या करोड़ो में है।स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। सितंबर 2024 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11.66 करोड़ घर-घर शौचालय बनाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में, **SBM-Urban** के अंतर्गत 63.63 लाख (लगभग 6.36 करोड़) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा, शहरी हिस्से में लगभग 6.36 लाख (636,000) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर 2.41 लाख से अधिक सामुदायिक सैनिटरी (सार्वजनिक) परिसर तैयार किए गए हैं। लगभग 5.87 लाख गाँवों को ओडीएफ ,+ स्टेटस मिला है, जहाँ सिर्फ खुले में शौच खत्म करने के बाद ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक किया जा रहा है। इस तरह की उपलब्धियाँ इस मिशन की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती हैं। लोगों की सोच शौचालय के प्रति जन दृष्टिकोण और जनता की सोच इस मिशन के बारे में मिश्रित है। कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण हैं, तो कुछ आलोचनाएँ भी।लोगो के सकारात्मक दृष्टिकोण है कि इसे मोदी सरकार की प्रमुख सफलता के रूप में देखते हैं ।उन्होंने दस वर्ष के अंदर लाखों-करोड़ों शौचालय बनवाए, जिससे पहले खुले में शौच करना सामान्य था और अब बहुत से गाँव और शहर ओडीएफ घोषित हुए हैं।महिलाओं और बच्चों की गरिमा में सुधार हुआ है। इज्जतघर का विचार सिर्फ भौतिक सुविधा नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन भी है।स्वास्थ्य पर असर भी सकारात्मक दिखता है ।बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों में कमी, और स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता बढ़ी है।.नकारात्मक और सतर्क दृष्टिकोण केवल लोगो का ही नही है। विपक्ष भी हमलावर है और देश का विकास उनको पच नही रहा है।कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद लोगो को मुलभुत सुविधा देने के लिए कभी सकारात्मक रुख नही अपनाया।जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ और समाजशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ निर्माण ही काफी नहीं है। आईएमपीआरआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई घरों में शौचालय बने होने के बावजूद, हर जगह उनका उपयोग नहीं हो रहा है। रख-रखाव की बड़ी समस्या है। कई शौचालयों में साफ-सफाई, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन नहीं हो पाता।व्यवहार परिवर्तन का काम अधूरा है। कुछ जगहों पर लोग फिर भी खुले में जाना पसंद करते हैं, या उपयोग न करने की आदत बन गई है क्योंकि उनकी निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी या सुविधाएँ सीमित थीं। मोदी सरकार को लोग कैसे देखते हैं ।मोदी सरकार को स्वच्छता को हिंदुस्तान की प्राथमिकता बनाने के लिए बहुत सम्मान मिला है। यह मिशन न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया गया है।सरकार के बजट और संसाधन आवंटन को एक गंभीर सरकारी प्रतिबद्धता माना गया है । कई लोगों के नज़र में यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ घोषणाएँ नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मिशन को पहचान मिली है, जिससे भारत की स्वच्छता छवि में सुधार हुआ है। कुछ आलोचक कहते हैं कि सरकार ने शुरुआत में पर्याप्त बजट नहीं दिया था, या आवंटन और रिलीज़ के बीच देरी रही। भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। निर्माण ठेकेदार, दलाल, स्थानीय मिस्त्रीगण और सरकारी एजेंसियाँ लाभ में शामिल हो सकती हैं।उपयोग और रख-रखाव के बाद की विस्तार योजनाओं (जैसे ओडीएफ प्लस) में जनता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी कुछ जगहों पर सुस्त है।भ्रष्टाचार, बिचौलिये और कमी समस्या के पहलूआज भी विधमान है।भ्रष्टाचार इस मिशन की चुनौतियों में एक बड़ी बाधा रही है। बिचौलियों और दलालों की भूमिका में ग्रामीणों के मजबूरी का फायदा उठाया गया है।कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि शौचालय निर्माण में स्थानीय दलाल और मिडिलमैन शामिल होते हैं। वे लाभ कमाने के लिए निम्न-मानक निर्माण सामग्री उपयोग करते हैं। ठेकेदारों और मिस्त्रीगण कभी-कभी गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी करते हैं, जिससे टॉयलेट की दीवारें, टैंक या सीटें खराब बनती हैं।दावा किया गया है कि लाभार्थियों को मिलने वाली राशि (वित्तीय सहायता) पूरी तरह गायब नहीं होती, बल्कि कुछ हिस्सा दलालों या ठेकेदारों के पास चला जाता है।जिसमे पंचायत के कार्मिक से लेकर उच्च अधिकारी और सरपंच शामिल रहते थे। यह वित्तीय हस्तक्षेप लोगों तक सीधा नहीं पहुँचने का कारण बनता है।इस वजह से, कुछ परिवारों के हाथ में आठ-दस हजार जैसा हिस्सा आता है, जबकि शौचालय निर्माण में खर्च उससे कहीं अधिक हो सकता है। यह लाभ विभाजन और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।दोष सिर्फ केंद्र सरकार को देना उचित नहीं है। राज्य सरकारें, पंचायत स्तर के अधिकारी, स्थानीय ठेकेदार और मिस्त्रीगण भी जिम्मेदार हैं। निगरानी तंत्र में कमज़ोरी रही है । तीसरे पक्ष की जांच, सतत निगरानी और जवाबदेही प्रणाली मजबूत नहीं रही है। लाभार्थियों की भागीदारी सीमित रही है।सामाजिक जांच और समुदाय-नेतृत्व को और बढ़ाना चाहिए।विपक्षी दल और आलोचक इस मिशन को पूरी तरह नकार नहीं करते, लेकिन उनकी चिंताएँ स्पष्ट हैं। विपक्ष का मानना है कि बहुत से शौचालय निर्माण संख्या का खेल बन गए हैं।सिर्फ संख्या दिखाने के लिए निर्माण किया गया, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान कम गया। कुछ जगहों पर दो सीट वाला एक ही टॉयलेट जैसा विचित्र निर्माण मुद्दे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला सामने आया है। पर्याप्त राशि नहीं जारी की गई विपक्ष यह तर्क देता है कि केंद्र ने शुरू में पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया या राज्य और पंचायती स्तर पर फंड रिलीज़ में देरी की।

संपादकीय

न्यायसंगत आरक्षण

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार-बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर-जाल में फंसे परिवार-मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है। वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग-अलग होती है। ऐसी अवस्था में, सबसे निचले स्तर के लोग राज्य के संरक्षण पाने के लिये प्राथमिकता के हकदार हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच-समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है। इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा।

उपेक्षित संवेदनाओं और अनदेखें संघर्षों का सच

(लेखक- ललित गर्ग /)

(अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस- 19 नवम्बर, 2025)

महिला दिवस की तर्ज पर ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाने लगा है। पहला अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 1999 में 19 नवंबर को डॉ. जेरोम टीलकसिंह ने त्रिनिदाद और टोबैगो में मनाया था। दुनिया के 30 से अधिक देशों में यह दिवस मनाया जा रहा है। यह केवल पुरुषों का उत्सव नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक परिदृश्य में उनकी स्थिति, संघर्षों और मनोभावों को समझने का मौक़ा है। जैसे स्त्रियाँ वर्षों से असमानता, उपेक्षा और अन्याय के बोझ से जूझती रही हैं, वैसे ही आज पुरुष भी कई स्तरों पर अपने शोषण एवं उत्पीडित होने की बात उठा रहे हैं। महिलाओं की ही भांति अब पुरुषों पर भी उपेक्षा, उत्पीड़न एवं अन्याय की घटनाएं पनपने की बात की जा रही है। वे भी दबाव, अवसाद और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि पुरुषों की पीड़ा, उनके संघर्ष और उनकी संवेदनाएँ उतनी चर्चा का विषय नहीं बनते, जितना कि वे बनना चाहिए। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि समाज केवल स्त्रियों से ही नहीं, पुरुषों से भी बनता है और किसी एक की उपेक्षा पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम 'पुरुषों और लड़कों का उत्सव' है।आज का पुरुष बदलते समय के साथ एक दोहरी चुनौती से जूझ रहा है-एक ओर उससे पारंपरिक भूमिकाओं को निभाने की अपेक्षा की जाती है, दूसरी ओर नये सामाजिक ढाँचों में भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील, सहयोगी और सहचर होने का दबाव है। संघर्ष यह है कि इस परिवर्तन में उसकी पीड़ा, द्वंद्व और टूटन को गंभीरता से नहीं सुना जाता। उसे मजबूत, कठोर और समस्यारहित मान लेने का भ्रम उसकी वास्तविक जरूरतों को छिपा देता है। यही कारण है कि आधुनिक पुरुष स्वयं को कई बार दोयम दर्जे की स्थिति में पाता है-एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे समाज ज़िम्मेदारी तो देता है, पर अधिकार और संवेदना नहीं। पुरुषों पर हो रहे अत्याचारों की अनदेखी भी चिंताजनक है। घरेलू हिंसा, झूठे मुक़दमे, अभिभावकत्व के अधिकारों से वंचित होना, मानसिक प्रताड़ना, कार्यस्थलों पर उत्पीड़न-ये सब वास्तविक समस्याएँ हैं, जिन्हें अक्सर मज़ाक या अतिशयोक्ति कहकर टाल दिया जाता है। पुरुष के दर्द को 'मर्द को दर्द नहीं होता' जैसी रूढ़ि निगल जाती है। जबकि सच यह है कि भारत में पुरुष भी आत्महत्या, अवसाद और मानसिक दबाव के शिकार बन रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया है कि अवसाद और आत्महत्या के मामलों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है, पर इस पर चर्चा समाज की प्राथमिकता नहीं बनती। यह उपेक्षा न केवल अमानवीय है, बल्कि समाज के संतुलन को खतरे में डालने वाली भी है। कुछ वर्ष पूर्व भारत में सक्रिय अखिल भारतीय पुरुष एशोसिएशन ने भारत सरकार से एक खास मांग की कि महिला विकास मंत्रालय की भांति पुरुष विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाये। इसी तरह यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने यह मांग उठाई थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसी भी एक संवैधानिक संस्था बननी चाहिए। इन सांसदों ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र लिखने वाले एक सांसद हरिनारायण राजभर ने उस वक्त यह दावा किया था कि पत्नी प्रताड़ित कई पुरुष जेलों में बंद हैं, लेकिन कानून के एकतरफा रुख और समाज में हंसी के डर से वे खुद के ऊपर होने वाले घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर पुरुष इस तरह की अपेक्षाएं क्यों महसूस कर रहे हैं? लगता है पुरुष अब अपने ऊपर आघातों एवं उपेक्षाओं से निजात चाहता है। तरह-तरह के कानूनों ने उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाया है। जबकि आज बदलते वक्त के साथ पुरुष अब अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील हो चुका है। कई युवा पुरुष समाज-निर्माण की बड़ी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं और अपनी काबिलीयत व जुनून से यह साबित भी कर रहे हैं।

समाज हमेशा पुरुष से अपेक्षा करता है कि वह परिवार की रीढ़ बने, आर्थिक व भावनात्मक उत्तरदायित्व निभाए, कठिनाई में ढाल की तरह खड़ा रहे। लेकिन जब वही पुरुष कमज़ोर पड़ता है, टूटता है, या न्याय चाहता है, तो वह उपेक्षित कर दिया जाता है। पुरुष को यह अधिकार मिलना ही चाहिए कि वह अपनी पीड़ा कह सके, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और गलत आरोपों से मुक्त हो सके। जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा और न्याय के तंत्र बनाए गए, वैसे ही पुरुषों के लिए भी कुछ संवेदनशील और न्यायपूर्ण व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। यह समझना आवश्यक है कि पुरुष समाज के निर्माण का अभिन्न हिस्सा है-वह पिता है, पति है, पुत्र है, भाई है, मित्र है। उसकी उपस्थिति के बिना किसी भी परिवार या समाज की कल्पना अधूरी है। वह जिम्मेदारियों से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन इसी वजह से वह सबसे अधिक दबाव और अपेक्षाओं का भार उठाता है। यह भी सच है कि पुरुष ही समाज के विकास, विज्ञान, कला, परिश्रम और संरचना के बड़े हिस्से का वाहक रहा है। लेकिन इस योगदान के बावजूद, आज पुरुषों की समस्याओं के प्रति संवेदना बढ़ाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का संदेश यही है कि महिलाओं के समान ही पुरुषों की भी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और संवेदनाओं की रक्षा की जानी चाहिए। लैंगिक समानता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों पर बने अनुचित पूर्वाग्रहों को भी तोड़ना है। एक स्वस्थ, संतुलित समाज वही है जिसमें दोनों लिंगों की समस्याओं को समान रूप से सुना और समझा जाए। पुरुषों को कठोरता की बेड़ियों से मुक्त कर, उनके भावनात्मक अस्तित्व को स्वीकार करना समय की मांग है। पुरुष दिवस हमें जागरूक करता है कि सह-अस्तित्व, सहयोग, संवाद और करुणा ही पुरुष-स्त्री के संबंधों का वास्तविक आधार हैं। पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। इसलिए उनकी समस्याओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी पूरक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। जब समाज पुरुष की पीड़ा को भी उतनी ही गंभीरता से सुनेगा, जितनी वह स्त्री के आर्तनाद पर देता है, तभी हम सच्चे अर्थों में संतुलित और मानवीय समाज का निर्माण कर पाएँगे। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की तादाद कितनी है लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में जरूर काम कर रहे हैं।

मूल्य भावना का

भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे। हर सुबह वह भिक्षावृत्ति को निकलते तो उन्हें मार्ग में एक किसान अपने खेत में काम करता मिलता। अपने कार्य के प्रति उसकी निष्ठा देख बुद्ध के मन मं उसके लिए करुणा उमड़ी। वह प्रतिदिन वहां रुककर उस किसान को कुछ उपदेश देने लगे। जब उस किसान की फसल तैयार हुई तो उसने संकल्प किया कि वह अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को भेंट करेगा। दुर्योगवश उसी रात मूसलाधार वर्षा हुई और उसकी सारी फसल चौपट हो गई। अगले दिन जब भगवान बुद्ध वहां से गुजरे तो उन्होंने किसान को वहां रोता हुआ पाया। पूछने पर किसान उनको सारी घटना सुना कर बोला, ''प्रभु! मुझे दुख अपने नुक्सान का नहीं, वरन इस बात का है कि मैं आपकी सेवा का यह अवसर चूक गया''

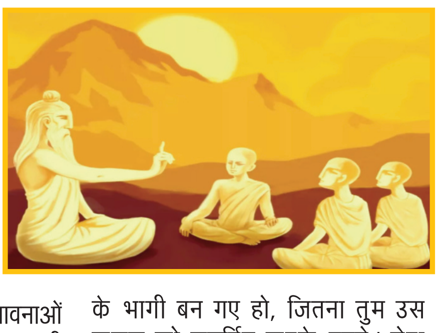

बुद्ध मुस्कराए और बोले, 'भंते! मूल्य वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का होता है। तुम्हारे हृदय में उमड़ी भावनाएं तो मुझ तक कल ही पहुंच गई थीं। इनके कारण तुम उससे ज्यादा पुण्य के भागी बन गए हो, जितना तुम उस फसल को समर्पित करके बनते। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है'' किसान की आंखें यह सुनकर नम हो उठीं।

विचार मंथन

बिखरा हुआ विपक्ष, अहंकार में डूबे क्षेत्रीय दल, भाजपा का अमृतकाल

(लेखक- सनत जैन)

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को 202 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह जीत भी तब मिली जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर पूरे बिहार में रैली निकालकर जन जागरण का काम किया। चुनाव-प्रचार के दौरान सरकार के खिलाफ भारी विरोध जनता के बीच में देखने को मिला। उसके बाद भी एनडीए गठबंधन की यह जीत सभी को आश्चर्यचकित कर रही है। यह चमत्कार कैसे हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार में जिस तरह की जीत मोदी और शाह की जोड़ी ने हासिल की है, उसे देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा है कि राज्यों में भाजपा अपनी ही सरकार बनाकर 2047 तक का जो सपना उन्होंने देखा है उसे साकार करने में लग गई है। केंद्र एवं राज्य में भाजपा की ही सरकार हो इसके लिए जो रणनीति 2017 से भाजपा और संघ बना रहा था वह पूरी तरीके से परवान चढ़ चुकी है। लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा से एक गलती हुई थी, कि उसने यह मान लिया था कि 300 सीटों पर उसका कब्जा है। उसने उन 100 सीटों पर ध्यान दिया था, जहां से वह 400 सीट का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ जो वातावरण बन गया था उसमें 300 सीटों को वह बचा के नहीं रख पाए। वहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और 240 सीटों पर आकर भाजपा रुक गई। इस गलती से भाजपा ने सबक लिया और अब उसने चुनाव आयोग के माध्यम से जीत की जो नई इबारत लिखना शुरू की है उसका विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। विपक्षी दलों के बीच में यह कहा जा रहा है कि वो जाएं तो कहां जाएं, केंद्रीय चुनाव आयोग में जो आयुक्त हैं वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो याचिका लगी हैं उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। संसद के 141 सदस्यों को बर्खास्त कर सरकार ने संसद से चुनाव कानून पास कराया था। चुनाव आयुक्तों के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है। सरकार ने कानून बनाकर उसे असीमित शक्तियां दे दी हैं। ऐसे में कहा जा रहा, कि न्याय पालिका से अब जो भी न्याय मिल रहा है वह सरकार को मिल रहा है। न्याय पालिका विपक्ष के ऊपर आक्रामक है। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां जिस तरीके से विपक्ष को निशाने पर लेती हैं, न्यायपालिका से उन्हें संरक्षण मिलता है। ऐसी स्थिति में एक-एक करके समस्त विपक्षी दलों के नेता और क्षेत्रीय दलों के नेता भाजपा के निशाने पर हैं। एक-एक करके उन राज्यों में भी भाजपा बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती जा रही है जहां पर भाजपा का पहुंच पाना संभव ही नहीं था। इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है। चुनाव आयोग कई ऐसे सॉफ्टवेयर उपयोग में ला रहा है जो चुनाव में मनमाफिक चुनाव परिणाम मशीन की सहायता से ला सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूरी चुनाव व्यवस्था का केंद्रीय कारण कर लिया है। चुनाव आयोग में जो भी डिजिटाइजेशन है उस पर चुनाव आयोग का ही नियंत्रण है। ईवीएम मशीन, वीवीपेट, मतदाता सूची और मतगणना सभी पर केंद्रीय चुनाव आयोग का नियंत्रण है। चुनाव आयोग से संबंधित कार्यों के लिए जो ईवीएम मशीन और वीवीपेट वगैरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनमें भाजपा के ही पदाधिकारी सदस्य बनकर काम कर रहे हैं। मतदान, मतगणना और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी तथ्यों के साथ पत्रकार वार्ता करके जो गड़बड़ियां की गई हैं उन्हें उजागर कर चुके हैं। एड़ीआर ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 80 लोकसभा सीटों पर मतदान और मतगणना के परसेंटेज और चुनाव परिणाम को लेकर चुनाव आयोग को जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसे भी चुनाव आयोग ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी जब ये मामले जाते हैं तब इन मामलों पर तारीख पर तारीख मिलती है। सुनवाई और फैसला किसी मामले में नहीं होता है। इस स्थिति में विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की मूर्खता और सत्ता लोलुपता के कारण भाजपा को दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाती चली जा रही है। उड़ीसा जैसे राज्य में जिस तरह से भाजपा ने सत्ता हासिल की है, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने ही सहयोगी दलों को एक तरह से खत्म कर दिया है। बिहार के भी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भले नीतीश बाबू की पार्टी दूसरे नंबर की हो लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर भाजपा ने सेंध लगा दी है उसमें नीतीश बाबू भी फड़फड़ा रहे हैं। अब उनके पास भी उनका और उनकी पार्टी का कोई स्वतंत्र आधार नहीं रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा अच्छी तरह से जानती हैं जब तक कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में है तब तक उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। 75 वर्षों के बाद भी कांग्रेस आज 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों में प्रभावशाली है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार

मुंबई ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन गैरेज वेंचर्स लिमिटेड ने बड़ा मुकाम हासिल किया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया। ग्रो के शेयरों में चौथे दिन भी तेजी रही और यह 14.37 फीसदी बढ़कर 169.87 रुपए तक पहुंचा। आईपीओ लिस्टिंग के बाद से ग्रो के शेयर अब तक लगभग 50 फीसदी ऊपर और अपने इश्यू प्राइस से 78 फीसदी से अधिक बढ़ चुके हैं। आईपीओ 4 से 7 नवंबर तक खुला और 95-100 रुपए प्रति शेयर की कीमत तय की गई थी। इसका कुल सब्सक्रिप्शन 17.6 गुना हुआ, जिसमें योग्य संस्थागत खरीदारों ने 22.02 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों ने 14.20 गुना रुचि दिखाई। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रो का मजबूत बिजनेस मॉडल, आसान ऐप इंटरफेस और ग्राहक-केंद्रित सेवाएं इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। कंपनी लगातार नई सुविधाएं जोड़ रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं की संख्या और कमाई तेजी से बढ़ रही है। ग्रो अब मार्जिन ट्रेडिंग, शेयरों के बदले लोन, पर्सनल लोन, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसी नई सेवाओं का विस्तार कर रहा है। शुरुआती चरण में ही ये सेवाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, भविष्य में इसके और भी बढ़ने की संभावना है।

फिजिक्सवाला के आईपीओ की शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत

145 रुपए पर लिस्ट हुए शेयर, हर लॉट पर दिया 4932 रुपए का फायदा

नई दिल्ली एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ के शेयर मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत के साथ लिस्ट हो गए। कंपनी के शेयर एनएसई पर 145 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए। यह आईपीओ प्राइस बैंड के अपर एंड 109 रुपये से 36 रुपये या 33 फीसदी ज्यादा है। वहीं बीएसई पर कंपनी के शेयर 143 रुपये पर लिस्ट हुए, यह प्राइस बैंड की तुलना में 34 रुपये या 31 फीसदी ज्यादा है। फिजिक्सवाला आईपीओ की लिस्टिंग ग्रे मार्केट अनुमानों से काफी बेहतर रही। लिस्ट होने से पहले ग्रे मार्केट में फिजिक्सवाला आईपीओ के शेयर 123 रुपये पर चल रहे थे। यह प्राइस बैंड से 14 रुपये का प्रीमियम था। इसी के साथ निवेशकों को तगड़ा लिस्टिंग गेन भी मिला है। फिजिक्सवाला आईपीओ के एक लॉट में 137 शेयर थे। इस तरह निवेशकों को हर लॉट पर 4,932 रुपये का फायदा हुआ है।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 2 पैसे की बढ़त के साथ ही 88.57 पर बंद हुआ। वहीं शुरुआती कारोबार में आठ पैसे कमजोर होकर 88.67 प्रति डॉलर पर आ गया। वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.67 प्रति डॉलर पर खुला और फिर 88.69 प्रति डॉलर पर लुढ़क गया। हालांकि बाद में संभलता हुआ 88.68 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से आठ पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.59 पर बंद हुआ। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.43 पर आ गया।

भारत का जीसीसी वर्कफोर्स 2030 तक 3.46 मिलियन के आंकड़े को छूने का अनुमान

नई दिल्ली

58 प्रतिशत से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) अब एआई पायलेट से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इसके साथ भारत में सेक्टर में वर्कफोर्स के 2030 तक 3.46 मिलियन के आंकड़े को छूने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे करीब 1.3 मिलियन नए जॉब रोल पेश करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष 2025 में करीब 70 प्रतिशत जीसीसी पहले से ही जेनेरेटिव एआई (जेनएआई) में निवेश कर रहे हैं, जबकि 60 प्रतिशत जीसीसी 2026 तक एक डेडिकेटेड एआई सेफ्टी और गवर्नेंस टीम को सेट अप करने की योजना में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस देश के जीसीसी में तेजी से संस्थागत हो रहे हैं।

अनुमान है कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव 2026 में नौकरियों पर दिखेगा, जहां अवसरों में 11 प्रतिशत की बढ़त दिखेगी और सेक्टर में लोगों की संख्या 24 लाख होगी। भारत अपनी जीसीसी 4.0 यात्रा को लेकर क्रिटिकल इंटरसेक्शन पर है, जहां देश स्केल, स्किल और टैलेंट का एक यूनिक तालमेल बना रहा है। आज के समय में जीसीसी न केवल एआई को एक्सप्लोर कर रहे हैं बल्कि कई लोग डिप्लॉय कर चुके हैं और कई डिप्लॉय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 33 प्रतिशत जीसीसी ने सेंट्रल एआई कमेटी और सीओई

तैयार कर लिए हैं। वहीं, 29 प्रतिशत जीसीसी ऑडिट और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत बिजनेस यूनिट के जरिए ओवरसाइट को मैनेज कर रहे हैं।

श्रीलंका को एडीबी से 30 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मिली

राशि तीन किस्तों में वितरित की जाएगी

कोलंबो श्रीलंका ने मंगलवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का समझौता किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश की वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और सुधार को सुदृढ़ करना है, जिससे केंद्रीय बैंक की नियामक क्षमता मजबूत हो सके। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों का समर्थन भी किया जाएगा। इसका लक्ष्य श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करना है। एडीबी सहायता का एक हिस्सा त्रिंकोमाली के पूर्वी बंदरगाह क्षेत्र और सिगिरिया के आसपास पर्यटन क्षमता के विकास के लिए लगाया जाएगा। इसमें नीति-आधारित ऋण और निवेश ऋण दोनों शामिल होंगे, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन राजस्व में सुधार संभव हो। श्रीलंका 2022 के गंभीर वित्तीय संकट के बाद आईएमएफ समर्थित सुधारों को लागू कर रहा है।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू

मुंबई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) 25 दिसंबर से अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा और पहले दिन करीब 23 विमान उड़ान भरने वाले हैं। इसकी जानकारी एयरपोर्ट की ओर से दी गई। एयरपोर्ट की ओर से बताया गया कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले महीने में एनएमआईए 12 घंटे (सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे) तक सक्रिय रहेगा और करीब 23 शेड्यूल उड़ानों को प्रति दिन संभालेगा। इस अवधि के दौरान एयरपोर्ट अधिकतम 10 फ्लाइट मूवमेंट प्रतिघंटा संभालेगा। पहले दिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत बेंगलुरु से आने वाली उड़ान इंडिगो से होगी, जो कि एनएमआईए पर सुबह 8 बजे उतरेगी। इसके बाद इंडिगो की उड़ान हैदराबाद के लिए सुबह 8:40 पर उड़ान भरेगी, जो कि इस एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट ने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के पहले महीने से ही इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को देश के 16 शहरों से कनेक्ट करेंगी। फरवरी 2026 से एयरपोर्ट 24 घंटे ऑपरेट करना शुरू करेगा और करीब 34 उड़ानें प्रतिदिन देखने को मिलेंगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की तैनाती 29 अक्टूबर, 2025 से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर को एनएमआईए का उद्घाटन किया गया था। एनएमआईए, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) के बीच एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) है।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 277, निफ्टी 103 अंक नीचे आया

मुंबई

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही मुनाफावसूली हावी होने से भी बाजार नीचे आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 277.93 अंक नीचे आकर 84,673.02 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 103.40 अंक की गिरावट के साथ ही 25,910.05 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में भारती एयरटेल,एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स,पावर ग्रिड, टाइटन और मारुति सुजुकी के शेयर लाभ में रहे जबकि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, ट्रेंट, एचयूएल, एचसीएल टेक, बीईएल और एचडीएफसी बैंक के शेयर नुकसान में रहे। लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 358.50 अंक की गिरावट के साथ 60,822 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 192.85 अंक की गिरावट के साथ 18,154.75 पर बंद हुआ। सेक्टोरल आधार पर आईटी, ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटीज के साथ करीब सभी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। वैश्विक स्तर पर बिकवाली हावी होने से भारतीय बाजारों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। दबाव बना हुआ है। अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने के कारण भी दुनिया भर के बाजारों पर दबाव बना हुआ है।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट पर खुले। वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 85,042 अंक पर

खुला। लेकिन खुलते ही लाल निशान में फिसल गया। सुबह शुरुआत में यह 135.58 अंक की गिरावट लेकर 84,815.37 पर कारोबार कर रहा था। इसी निफ्टी-50 मामूली बढ़त के साथ 26,021 अंक पर खुला। हालांकि, खुलते ही इसमें गिरावट देखने को मिली।

अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी ने ब्रोडर इंडेक्स पर दबाव डाला। डाउ जोंस 1.18 फीसदी, एसएंडपी 500 भी 0.92फीसदीकी गिरावट लेकर बंद हुआ और नैस्डैक 0.84फीसदीफिसला। वहीं एशियाई बाजारों में कमजोर कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 2.06 फीसदी नीचे था। चीन का सीएसआई 300 इंडेक्स 0.15 फीसदी गिरा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.85 फीसदीत टूट गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.33 फीसदी गिरा।

आरजे कॉर्प आंध्र प्रदेश के नायडूपेटा में 1,743 करोड़ का सौर प्लांट लगाएगा

राज्य सरकार ने 37 एकड़ भूमि रियायती दर पर दी

नई दिल्ली

कारोबारी समूह आरजे कॉर्प ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश करते हुए सौर विनिर्माण में कदम रख दिया है। समूह की इकाई वोल्टसन लैब्स आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नायडूपेटा में 1,743 करोड़ रुपये की लागत से सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। यह प्लांट नायडूपेटा एमपीएसईजेड में लगाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने परियोजना को तेज़ी से शुरू करने हेतु रियायती दर पर 37 एकड़ भूमि आवंटित की है। आरजे कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी पेप्सिको बॉटलर के रूप में जानी जाती है और भारत में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे प्रमुख क्यूएसआर ब्रांडों का संचालन करती है। समूह का पोर्टफोलियो डेयरी (जर्सी ब्रांड), सोलर प्रसंस्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और रियल एस्टेट तक फैला है, जिसका अनुमानित मूल्यांकन 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है। राज्य सरकार के अनुसार, वोल्टसन का यह निवेश न केवल भारत के अक्षय ऊर्जा भविष्य में विश्वास दिखाता है, बल्कि आंध्र प्रदेश की नीतियों, प्रशासन और 'कारोबार करने की गति' में भरोसा भी दर्शाता है। कंपनी द्वारा विकसित की जा रही यह इकाई 2 गीगावॉट के एकीकृत सोलर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देगी। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जहां प्रत्येक चरण में

1 गीगावॉट सौर सेल और 1 गीगावॉट मॉड्यूल क्षमता शामिल होगी। वोल्टसन लैब्स अत्याधुनिक टॉपकॉन मोनोक्रिस्टलाइन और बाइफेसियल तकनीकों का उपयोग करेगी, जिससे भारत में उच्च मूल्य के सौर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

नई इनकम टैक्स एक्ट में होगा बदलाव, टैक्स फॉर्म होंगे आसान और पारदर्शी

मुंबई भारत में 1 अप्रैल 2026 से पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू होगा। संसद ने यह कानून 12 अगस्त 2025 को पास किया था। सीबीडीटी के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत टैक्स रिटर्न फॉर्म और अन्य सभी फॉर्म को पूरी तरह से सरल बनाया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि नए आईटीआर फॉर्म, टीडीएस की तिमाही रिटर्न और अन्य फॉर्म्स को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिवीजन मिलकर काम कर रहे हैं। लक्ष्य है कि जनवरी 2026 तक सारे फॉर्म और नियम तैयार हो जाएं, ताकि टैक्सपेयर अपने सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया बदलने के लिए पर्याप्त समय पा सकें। नए फॉर्म कानून विभाग से पास होने के बाद नोटिफाई किए जाएंगे और संसद के सामने रखे जाएंगे। पुराने एक्ट में 819 सेक्शन और 47 चैप्टर थे, जबकि नए कानून में यह घटकर 536 सेक्शन और 23 चैप्टर रह गए हैं। शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटकर 2.6 लाख हो गई है। नए कानून में 39 नई टेबल और 40 नए फॉर्मूला जोड़े गए हैं, जिससे लंबे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। नए कानून में कोई टैक्स दर नहीं बढ़ाई गई है, केवल भाषा और स्ट्रक्चर सरल किया गया है।

ईसीएमएस के तहत सरकार ने 17 नए विनिर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत मंगलवार को 17 नए आवेदनों को मंजूरी प्रदान की, जिससे योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इन नई विनिर्माण इकाइयों में कैमरा मॉड्यूल उत्पादन के 3 संयंत्र, मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (एमएलपीसीबी) के 9 संयंत्र, ऑप्टिकल ट्रांसीवर विनिर्माण की 2 इकाइयां तथा मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाले अहम पुर्जों के निर्माण वाली इकाइयां शामिल हैं। इन परियोजनाओं में कुल 7,172 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है, जबकि इनसे 65,111 करोड़ रुपये के उत्पादन की संभावना जताई गई है। नए संयंत्र गोवा, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक ढांचे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रमुख स्वीकृत कंपनियों में एक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैबिल सर्किट इंडिया, जेटवर्क की सहायक कंपनियां जेटफैब इंडिया और जेटकेम सप्लाई चेन सर्विसेज, यूनो मिंडा तथा सिरमा एसजीएस की सहायक सिरमा मोबिलिटी शामिल हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी

एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना में सभी घटकों को शामिल करने के बजाय सरकार ने एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और केवल उन पुर्जों पर ध्यान केंद्रित किया जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सितंबर तिमाही में तेज हुई प्रवर्तकों की हिस्सेदारी बेचने की रफ्तार

932 सूचीबद्ध कंपनियों के अध्ययन में सामने आई प्रवृत्ति

नई दिल्ली

सितंबर 2024 में समाप्त हुई तिमाही के दौरान प्रवर्तकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने की रफ्तार दूसरी लगातार तिमाही में और तेज हो गई।

विश्लेषण के अनुसार, लगभग 4.6 फीसदी कंपनियों में प्रवर्तकों ने अपनी हिस्सेदारी एक फीसदी या उससे अधिक घटाई। यह बदलाव स्टॉक ऑप्शन जैसे नियमित लेन-देन से अलग उन मामलों को दर्शाता है जहां हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण कटौती देखी गई है। यह अध्ययन 932 कंपनियों के दीर्घकालिक शेयरधारिता रिकॉर्ड पर आधारित है, जिनमें बीएसई 500, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांकों की कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर तिमाही में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी बिक्री का अनुपात अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में अधिक रहा और यह मार्च तिमाही के स्तर से दोगुने से भी ज्यादा पर पहुंच गया। महामारी के बाद आए बाजार उछाल के दौरान ऊंचे मूल्यांकन स्तरों पर की गई बिकवाली की प्रवृत्ति सितंबर 2024 में अपने चरम पर दिखाई दी। बाजार के जानकारों के अनुसार प्रवर्तक हिस्सेदारी में कमी को केवल मूल्यांकन के चरम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई प्रवर्तकों की अधिकांश व्यक्तिगत संपत्ति उनकी ही कंपनियों में निवेशित रहती है, इसलिए वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए हिस्सेदारी बेचते हैं। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में प्रवर्तकों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। पहले प्रवर्तक अक्सर गैर-पारदर्शी तरीकों से धन निकालते थे, जिससे अल्पांश शेयरधारकों पर असर पड़ता था। अब लाभप्रदता और पारदर्शिता को महत्व मिलने के कारण अधिक मूल्य सृजन हो रहा है, जबकि औपचारिक वेतन के अतिरिक्त नकदी प्राप्त करने की उनकी क्षमता सीमित हुई है।

बायजू अल्फा से गायब करोड़ों! नई याचिका में रवींद्रन पर गंभीर आरोप

ब्रिटेन की खरीद फर्म ओसीआई के साथ हुए एक समझौते से जुड़ा मामला

नई दिल्ली

डेलावेयर दिवालिया अदालत में दायर एक नई याचिका में बड़ा दावा किया गया है कि बायजू अल्फा के लेखे से गायब हुए 53.3 करोड़ डॉलर का बड़ा हिस्सा कथित रूप से 'राउंड-ट्रिपिंग' के जरिए इसके संस्थापक बैजू रवींद्रन और उनके सहयोगियों के पास वापस पहुंचा। यह आरोप उस पहले दिए गए शपथ पत्र से मेल नहीं खाता, जिसमें कहा गया था कि धनराशि का उपयोग वैध कॉरपोरेट आवश्यकताओं के लिए किया गया था।

याचिका वादी बायजू अल्फा के ऋणदाता और हस्तक्षेपकर्ता ग्लास ट्रस्ट कंपनी ने बताया कि यह मामला ब्रिटेन की खरीद फर्म ओसीआई लिमिटेड के साथ हुए एक समझौते से जुड़ा है। इस कंपनी को विवादित धन का बड़ा हिस्सा मिला था।

ज्ञात हो कि बायजू अल्फा एक विशेष प्रयोजन हेतु बनाई गई कर्ज लेने वाली इकाई, ने टर्म लोन-बी लिया था और वर्तमान में इसका नियंत्रण ऋणदाताओं के पास है। 53.3 करोड़ डॉलर की वसूली के प्रयास में, कंपनी ने ओसीआई लिमिटेड और इसके पूर्व प्रतिनिधि रूपिन बैंकर पर मुकदमा दायर किया है।

समझौते के तहत ओसीआई के संस्थापक ने शपथ पत्र दायर कर कहा कि उन्हें अल्फा से मिली राशि का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया है। उनकी समीक्षा के अनुसार धनराशि कई चरणों में सिंगापुर स्थित एक कॉरपोरेट इकाई बायजू ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की गई, जिसका स्वामित्व कथित रूप से बैजू रवींद्रन से जुड़ा है।

याचिका में आरोप है कि यह लेनदेन दर्शाता है कि रवींद्रन कॉरपोरेट संपत्तियों का निजी उपयोग हेतु दुरुपयोग करने की साजिश में शामिल थे।

इसमें कहा गया कि अब जब ओसीआई आगे आ रहा है, तो गायब धन की सच्चाई सामने पड़ रही है यानी अधिकांश धन अंततः रवींद्रन और उनके सहयोगियों को लौटा दिया गया था।

अक्टूबर में भारत के व्यापार घाटे में बड़ी वृद्धि, निर्यात घटा और आयात बढ़ा

व्यापार घाटा 41.68 अरब डॉलर तक पहुंचा, निर्यात में 11.8 फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली

वाणिज्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 34.38 अरब डॉलर पर आ गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.8 फीसदी कम है। अमेरिका को होने वाले निर्यात में भी गिरावट देखी गई, जो 6.9 अरब डॉलर से घटकर 6.3 अरब डॉलर रह गया। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और प्रमुख बाजारों में कमजोर मांग के कारण भारतीय उत्पादों की विदेशों में बिक्री प्रभावित हुई है। दूसरी ओर, अक्टूबर में आयात 76.06 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.63 फीसदी अधिक है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कीमती धातुओं, विशेषकर सोने और चांदी के आयात की रही। सोने का आयात 4.92 अरब डॉलर से बढ़कर 14.72 अरब डॉलर हो गया, जबकि चांदी के आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इनकी वजह से कुल आयात पर दबाव बढ़ा और व्यापार घाटा बढ़कर 41.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) के आंकड़े थोड़े संतोषजनक हैं। इस अवधि में कुल निर्यात 0.63 फीसदी बढ़कर 254.25 अरब डॉलर और आयात 6.37 फीसदी बढ़कर 451.08 अरब डॉलर हो गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बीसीसीआई का बड़ा फैसला, राजनीतिक तनाव के चलते भारत-बांग्लादेश महिला क्रिकेट सीरीज रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच अगले महीने होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज को बीसीसीआई ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। बोर्ड अब दिसंबर में टीम इंडिया के लिए एक वैकल्पिक सीरीज कराने के विकल्प तलाश रहा है।

आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम (FTP) के तहत यह सीरीज कुल 6 मैचों- 3 वनडे और 3 टी20 की थी, जिन्हें कोलकाता और कटक में आयोजित किया जाना था।

सीरीज क्यों टली?

बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, भारत-बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव इस फैसले की बड़ी वजह हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश में एक अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इसी राजनीतिक उथल-पुथल से दोनों देशों के संबंध भी प्रभावित हुए हैं।

ढाका की अंतरिम सरकार ने हसीना को भारत से सौंपने की मांग भी की है, जिसके चलते माहौल और गंभीर हो गया है।

बीसीसीआई और बीसीबी की प्रतिक्रिया

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: 'हम दिसंबर में वैकल्पिक सीरीज आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पर काम जारी है।'

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी पुष्टि की कि उन्हें सीरीज स्थगित होने की जानकारी बीसीसीआई से मिल चुकी है और वे नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं।

पहले भी टल चुका है भारत का बांग्लादेश दौरा

इससे पहले, अगस्त 2025 में होने वाला भारतीय पुरुष टीम का सफेद गेंद का दौरा भी सितंबर 2026 तक टाल दिया गया था क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते हसीना सरकार गिर गई थी।

भारत के लिए बड़ी बाधा

यह महिला टीम के लिए विश्व कप जीत के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होनी थी। यह सीरीज महिला ओडीआई चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत भी करती।

भारत में 17 दिसंबर से होगी विश्व टेनिस लीग, मेदवेदेव और बोपन्ना सहित कई स्टार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

बेंगलुरु (एजेंसी)। पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन दानिल मेदवेदेव और 2022 की विंबलडन चैंपियन एलेना रयबाकिना सहित कई शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहां 17 दिसंबर से होने वाले विश्व टेनिस लीग (WTL) में भारतीय प्रशंसकों के सामने अपना जलवा दिखाएंगे।

इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2022 में की गई थी और पहली बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले इस चार दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता रहा है। मेदवेदेव और रयबाकिना के अलावा आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस, फ्रांसीसी स्टार गेल मोनफिल्स और पाउला बडोसा भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हाल ही में शीर्ष स्तर के टेनिस से संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, युकी भांबरी, अंकिता रैना, श्रीवल्ली भामिदीपती और माया रेवती लीग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

रयबाकिना ने कहा, 'मैंने भारत में टेनिस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं डब्ल्यूटीएल के साथ यहां अपनी शुरुआत करने के लिए रोमांचित हूं। मैं अपनी टीम के साथ कोर्ट पर हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार हूं।' WTL में चार टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेलेंगी। प्रत्येक मुकाबले में पुरुष एकल, महिला एकल और दो युगल मैच खेले जाएंगे। राउंड रोबिन के बाद शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी।

एशेज सीरीज 2-2 से बराबरी पर रहेगी : वॉन

लंदन (एजेंसी)। इसी माह 21 नवंबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने जा रही एशेज सीरीज के परिणामों को लेकर कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अपनी-अपनी अपनी राय रखनी शुरु कर दी है। इसी कड़ी में अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का भी बयान आया है। इसमें वॉन ने कहा है कि दोनो ही टीमें सीरीज में सीरीज 2-2 से बराबरी पर रहेगी। पांच मैचों की इस सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला है। वॉन ने भविष्यवाणी की है कि एशेज सीरीज में दोनो ही टीमें दो-दो मैच जीतेंगी जबकि एक मैच बराबरी पर रहेगा। वॉन के अनुसार मेहमान टीम इंग्लैंड पर्थ में सीरीज के पहले मैच में जीत दर्ज करेगी, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड नहीं खेलेंगेहै। वॉन ने सोशल मीडिया में लिखा, अगर स्टोक्स फिट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगर सीरीज से पहले कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता, तो यही भविष्यवाणी बनी रहेगी।

कमिंस अभी पीठ की चोट से उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। वहीं इससे पहले वॉन ने कहा था कि हेजलवुड के बाहर होने के बाद इंग्लैंड की स्थिति पहले से बेहतर है।

वॉन ने तब कहा था, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेजलवुड और कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं। इससे इस सीरीज में इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो गया है। ऐसे में पर्थ में उनके लिए एक अंक आगे जाने का बड़ा अवसर है। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में केवल मिचेल स्टार्क ही पूरी तरस से फिट पहली पसंद के तेज गेंदबाज हैं, जबकि स्कॉट बोलैंड बैकअप खिलाड़ी हैं। हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडरों कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में अवसर दे सकता है। वहीं अनकैप्ड तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं।

गावस्कर ने कहा कोलकाता टेस्ट में पिच को दोष देना गलत

-कोच गंभीर को भी बचाव किया

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि कोलकाता टेस्ट में पिच का बचाव करने का मुख्य कोच गौतम गंभीर का फैसला बिलकुल सही है। गावस्कर ने कहा कि पिच को बिना कारणों के दोष दिया जा रहा है। पिच खतरनाक नहीं थी। रही भारतीय बल्लेबाज़ों के विकेट खोने की बात तो वे टेम्परामेंट और तकनीक की कमी के कारण असफल रहे।

कोलकाता टेस्ट तीन दिन भी नहीं चला। इस मैच में भारतीय टीम 124 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 93 रन ही बना पायी।.

इस मैदान की पिच पहले ओवर से ही अनियमित उछाल और टर्न का सामना कर रही थी। गंभीर ने कहा कि पिच में कमी नहीं थी। उन्होंने सीधा दोष बल्लेबाज़ों पर रखा और कहा कि उनसे इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी।

गावस्कर ने कहा, मैं गंभीर से पूरी तरह सहमत हूं। 124 रन इस पिच पर हासिल किये जा सकते थे। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पिच क्या कर रही थी पर अगर आपने देखा हो कि साइमन हार्मर एक ओवर में कितनी गेंदें टर्न करा रहे थे? वह गेंदों में बहुत बदलाव कर रहे थे। वह सीधी गेंद फेंक रहे थे और कभी-कभी एक गेंद को टर्न करा देते थे।.

गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाज़ों के स्वभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बहुत जल्दी बड़े शॉट खेलने के प्रयास कर रहे थे। दन्होंने कहा, यह कोई खतरनाक टर्निंग पिच नहीं थी. यह ऐसी पिच थी जिस पर आपको पांच दिन का टेस्ट खेल रहे हों, ऐसा बल्लेबाज़ी करनी थी, न कि 50 ओवर या टी20 की तरह कि तीन डॉट गेंदों के बाद आप बड़ा शॉट खेलने लग जाएं। यही मुख्य समस्या है। 124 रन भारत की इस बल्लेबाज़ी लाइन-अप के साथ कम से कम पांच विकेट रहते हासिल कर लिए जाने चाहिए थे।

गावस्कर ने कहा, मैं गौतम गंभीर से पूरी तरह सहमत हूं कि पिच में कुछ भी गलत नहीं था। तीसरे दिन एक-दो गेंद का टर्न होना सामान्य है। महाराज की कितनी गेंदें टर्न हुईं? जडेजा या अक्षर की कितनी गेंदें टर्न हुईं? लोग इसे स्पिनिंग पिच कह रहे हैं, जबकि इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं था।खराब

तकनीक और खराब टेम्परामेंट के कारण भारतीय टीम इस मैच में हारी।

वहीं इससे पहले कई पूर्व क्रिकेटरों चेतेश्वर पुजारा, हरभजन सिंह आदि ने पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि इसपर बल्लेबाजी करना संभव नहीं था।

भारत-दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट के समय में नजर आयेंगे बदलाव

लंच ब्रेक से पहले होगा टी ब्रेक

गुवाहाटी । भारत और इंग्लैंड के बीच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में समय के साथ ही अन्य कुछ बदलाव भी नजर आयेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने यहां के मौसम को देखते हुए समय में ये बदलाव किया गया है। इसके तहत ही ये मैच सुबह 9 बजे शुरु होगा जबकि आमतौर पर भारत में मैच 9.30 पर शुरु होते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण समय में बदलाव किया है। इसी के तहत ही गुवाहाटी में टॉस सुबह 8-30 बजे कराया जाएगा और फिर पहली गेंद 9 बजे फेंकी जाएगी। पांचों दिन पहला सत्र 9 से 11 बजे तक होगा। इसके बाद 20 मिनट का चाय का ब्रेक होगा। दूसर सत्र 11.20 बजे से 1.20 बजे तक चलेगा। दूसरे सत्र की समाप्ति के बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा। फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अंतिम सत्र होगा। यदि तय समय में पूरे ओवर नहीं होते हैं तो खेल को आधा घंटा आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार मुकाबला शाम 4.30 बजे तक आगे बढ़ सकता है. ये पहली बार होगा जब किसी टेस्ट में पहले टी ब्रेक और फिर लंच ब्रेक होगा। इसी को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, यह व्यावहारिक फैसला है। सर्दियों के समय पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाते हैं। शाम 4 बजे तक रोशनी काफी कम हो जाती है और उसके बाद ज्यादा खेलनो संभव नहीं हो पाता है। इसी चलते हमने इस टेस्ट मैच को जल्दी शुरू करने का फ़ैसला लिया है। इस सीरीज का पहला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली है। ऐसे में भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच को जीतना रहेगा।

दूसरे टेस्ट में शुभमन का खेलना तय नहीं, नितीश किये जा सकते हैं शामिल

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट में खेलने की संभावना कम है। ऐसे में इस मैच में ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को शामिल किया जा सकता है। शुभमन की गर्दन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान जकड़न आ गयी थी। इस कारण वह अस्पताल में भी भर्ती थे हालांकि अब वह होटल वापस आ गये हैं पर अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका दूसरे टेस्ट में गुवाहाटी में खेलना तय नहीं है। वहीं रेड्डी को ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था पर अब उनकी वापसी होने की संभावना है।

नितीश कोलकाता टेस्ट मैच से पहले बीसीसीआई ने रिलीज कर भारत ए के के लिए खेलने के लिए कहा था। वहीं शुभमन के फिट नहीं होने के कारण बोर्ड ने उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए शामिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वह 18 नवंबर को ईडन गार्डन्स में वैकल्पिक सत्र में अभ्यास भी करेंगे.

रेड्डी ने भारत ए की ओर से दो लिस्ट ए मैच खेले और जबकि उन्हें दूसरे मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने पहले मैच में 37 रन बनाए थे 18 रन देकर एक विकेट लिया था। टेस्ट टीम में फिर से शामिल पर वह 19 नवंबर को होने वाले भारत ए के तीसरे मैच में नहीं खेलेंगे।

वहीं शुभमन के बाहर होने से टीम की बल्लेबाजी कमजोर हुई है और इसी कारण रेड्डी जोड़ा जा रहा है। शुभमन अभी गर्दन के दर्द से उबर रहे हैं। बोर्ड उनके कार्याभार प्रबंधन पर भी ध्यान रखे हुए है। भारतीय टीम के पास अन्य विकल्प के तौर पर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन भी हैं प रेड्डी को अंतिम ग्यारह में शामिल करने से निचले क्रम में बल्लेबाजी

को मजबूती मिलने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी कमजोर पड़ने से पहला टेस्ट तीन दिनों के अंदर ही समाप्त हो गया था।

अर्जुन तेंदुलकर ने सीनियर क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे किये

मुम्बई । गोवा की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में एक अहम उपलब्धि अपने नाम की है। अर्जुन ने इस मैच में सौराष्ट्र के हरविक देसाई को 45 रन पर आउट करने के साथ ही सीनियर क्रिकेट में अपने विकेटों का शतक पूरा किया। उन्होंने सीनियर क्रिकेट में अपना पहला विकेट जनवरी 2021 में हरियाणा के खिलाफ अपनी पुरानी टीम मुंबई की ओर से डेब्यू मैच में लिया था। अर्जुन ने मुंबई की ओर से केवल एक सीनियर मैच खेला हैं। इसके बाद वह गोवा चले गये थे। उन्होंने दिसंबर 2022 में राजस्थान के खिलाफ मैच में गोवा की ओर से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। अर्जुन ने रणजी ट्रॉफी में अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह ही डेब्यू में शतक लगाया था। अर्जुन ने रणजी डेब्यू से एक महीने पहले आंध्र प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए में

डेब्यू किया था। अर्जुन के नाम फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 48 विकेट हैं। उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 25 बल्लेबाजों को आउट किया है। अर्जुन के नाक टी20 में 27 विकेट हैं। अर्जुन आईपीएल 2021 की मिनी-नीलामी में अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस पहुंचे थे। उन्होंने आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में भी उन्हें उसी कीमत पर फिर से लिया था। अर्जुन ने 2023 में आईपीएल में डेब्यू किया और उस सीजन में 4 मैचों में 3 विकेट लि। उन्होंने आईपीएल 2024 में केवल एक मैच खेला था।

आईपीएल 2026 सत्र में टीम के भरोसे को सही साबित करना रहेगा मार्कराम का लक्ष्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने कहा है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से बेहतर प्रदर्शन का पूरा प्रयास करेंगे। मार्कराम 2025 सत्र में भी सुपर जायंट्स के साथ थे और उनका कहना है कि फ्रैंचाइजी के उन्होंने टीम में बनाये रहने से वह बेहद खुश हैं। मार्कराम ने गत सत्र में 13 मैचों में 34.23 की औसत और 148.83 के स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए थे जिसमें 5 अर्धशतक भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने चार विकेट भी लिए थे। इसी कारण उन्हें टीम ने अपने साथ रखा है।।

मार्करम ने कहा, मैंने पिछले साल लखनऊ फ्रैंचाइजी के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लिया। मैंने साथी खिलाड़ियों से बहुत अच्छी दोस्ती की और टीम के साथ कुछ महीने बिताए। इसलिए मुझे रिटेन किए जाने पर बहुत खुशी है और निश्चित रूप से उनके साथ एक और सत्र खेलने के लिए उत्साहित हूं।

उनसे यह भी पूछा गया कि टूर्नामेंट के इस सत्र वह किस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहेंगे। जिस पर उन्होंने कहा, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा होना होगा। मुझे नहीं लगता कि हम पिछले सत्र में बहुत पीछे थे। यहां-वहां कुछ पल और कुछ परिणाम अलग दिखते। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, आप नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुके होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से किसी भी चीज को ज़्यादा कठिन नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जो चीजें अच्छी कीं, उन्हें फिर से करने की कोशिश करें और कुछ और महत्वपूर्ण क्षण जीतें। इससे पहले कि आप जानते हैं, मुझे लगता है कि प्रतियोगिता हमारे लिए वास्तव में आशाजनक है। आईपीएल में हालांकि टीम को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिले। ऋषभ पंत ने कप्तान के रूप में पद संभाला, जहीर खान टीम के संरक्षक थे। फिर भी, टीम प्लेऑफ से चूक गई, अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही। अब टीम का लक्ष्य इस सत्र में वापसी करना रहेगा।

हर टूर्नामेंट में पदक हासिल करना संभव नहीं, मैं हमेशा भारत का समर्थन करती हूं : मनु भाकर

नई दिल्ली । दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को बरकरार न रख पाने को झटका करार देते हुए हमवतन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। भाकर ने कहा कि वह 'हर दिन नहीं जीत सकतीं'। हाल ही में संपन्न हुए इस टूर्नामेंट में 13 भारतीय पदक विजेताओं में मनु भाकर का शामिल न होना निशानेबाज़ी जगत के कई लोगों के लिए थोड़ा आश्चर्य की बात है। भाकर ने कहा, 'मैं विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन मैं शीर्ष तीन में जगह नहीं बना पाई। मेरी टीम की साथी ईशा सिंह ने पदक जीता। आप खेल में हर दिन जीत नहीं सकते। कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह जरूरी है कि भारत को पदक जीतना चाहिए और यह मेरे या किसी और के जीतने से जुड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक भारत कोई भी पदक जीत रहा है, मैं उसका हौसला बढ़ाते रहूंगी चाहे वह किसी भी खेल में हो।' इस 23 साल की पिस्टल निशानेबाज 'ASMITA (महिलाओं को प्रेरित करके खेल जगत में उपलब्धि हासिल करना) के सोशल मीडिया हैंडल के लॉन्च पर बोल रही थी। भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन इस साल कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं। इस साल अगस्त में एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भाकर ने 'ASMITA' पहल के बारे में कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के खेल से जुड़ने को लेकर लोगों की सोच को बदलने में मददगार होगा।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले मुरलीधर का रिकार्ड अभी टूटना संभव नहीं

-कोई भी गेंदबाज नहीं है करीब

मुम्बई (एजेंसी)। आजकल सीमित ओवरों के प्रारुप का चलन बढ़ गया है पर टेस्ट क्रिकेट का महत्व अब भी अपनी जगह पर बना हुआ है। टेस्ट प्रारुप में विकेट लेने के लिए गेंदबाज में कौशल के साथ ही धैर्य होना भी जरुरी होता है क्योंकि इस प्रारुप में बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं और टी20 प्रारुप की तरह हर गेंद पर शॉट लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। टेस्ट प्रारुप में सबसे अधिक विकेट का रिकार्ड श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम हैं। मुरली ने अपने करियर में अब तक कुल 800 विकेट लिए हैं जो अभी टूटना संभव नहीं हैं क्योंकि वर्तमान समय का कोई भी गेंदबाज उनके करीब नहीं है केवल इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन के नाम ही 704 विकेट हैं पर उन्होंने भी संन्यास ले लिया है।

। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट में 67 बार पांच विकेट और 22 बार दस विकेट लिए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न हैं। वार्न ने 145 मैचों में अपने 708 विकेट लिए। वहीं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, 704 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर है। सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की इस सूची में भारत टीम के दिग्गज स्पिर अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं पांचवे नंबर पर इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा और ऑस्ट्रेलिया के नैथन लियोन हैं। इन सभी के नाम 500 से ज्यादा विकेट हैं। भारत के आर अश्विन भी 537 विकेट के साथ ही इस सूची में शामिल हैं।

जर्मनी और नीदरलैंड ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर फीफा विश्व कप 2026 के लिए प्रवेश हासिल किया

म्यूनिख । जर्मनी और नीदरलैंड ने अपने अपने क्वालीफाइंग मुकाबले जीतकर फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के लिए प्रवेश हासिल कर लिया है। जर्मनी ने स्लोवाकिया को 6-0 से हराया जबकि नीदरलैंड्स ने लिथुआनिया को 4-0 से हराते हुए ग्रुप जी में पहला स्थान हासिल किया। जर्मनी की जीत में लेरॉय की अहम भूमिका रही। उन्होंने स्लोवाकिया के खिलाफ दो गोल किये। जर्मनी की ओर से पहला गोल 18 वें मिनट में निक वोल्टेमाडे ने किया। वहीहं सर्ज ग्नब्री ने 29वें मिनट में एक गोल कर अपनी टीम की बढ़त को और बढ़ा दिया। फ्लोरियन विट्र्ज ने 36वें और 41वें मिनट में दो गोल करते हुए जर्मनी को 4-0 से बढ़त दिला दी। ब्रेक के बाद रिडल बाकू ने 67वें मिनट में गोल दागा। मुकाबले के 79वें मिनट में असन ओउएड्रागो ने साने के शानदार शॉट के बाद गोल दागकर टीम को 6-0 से आगे कर दिया। इस प्रकार ये मुकाबला एकतरफा रहा। वहीं दूसरी ओर, ग्रुप-जी के मुकाबले में नीदरलैंड्स और लिथुआनिया के मैच में 16वें मिनट में तिजानी रेइंडर्स ने डच टीम की ओर से पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में कोडी गाकपो ने गोल कर बढ़त को बढ़ा दिया। वहीं जावी सिमंस ने 60वें मिनट में एक गोल किया। इसके 2 मिनट बाद ही डोनियल मालेन के गोल से नीदरलैंड्स की टीम 4-0 से आगे हो गयी।

हिंसा के बीच ढाका हवाई अड्डे पर 10 घंटे तक फंसे रहे भारतीय तीरंदाज, 7 महिलाएं भी शामिल थी

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय तीरंदाजों को उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब वे एशियाई चैंपियनशिप के बाद ढाका से देश लौटने के दौरान उड़ान रद्द होने के कारण लगभग 10 घंटे तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे। यही नहीं उन्हें हिंसा प्रभावित बांग्लादेश की राजधानी में बिना सुरक्षा के एक स्थानीय बस में बिठा दिया गया और बाद में उन्हें एक घटिया आश्रय स्थल में रुकना पड़ा।

भारत के 23 सदस्यीय दल के 11 सदस्य उड़ान में बार-बार हो रही देरी के कारण काफी परेशान रहे। इनमें दो नाबालिग सदस्य भी शामिल थे। इस बीच उन्होंने जिस एयरलाइंस से टिकट बुक किया था उसका भी उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिला। इस दल में सीनियर खिलाड़ी अभिषेक वर्मा, ज्योति सुरेखा और ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा भी शामिल थे। वे शनिवार को दिल्ली के लिए रात 9.30 बजे की उड़ान के लिए ढाका हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, लेकिन विमान में सवार होने के बाद उन्हें बताया गया कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है और वह उड़ान नहीं भर पाएगा।

यह वह समय था जब ढाका में सड़कों पर हिंसा देखी गई थी, क्योंकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विशेष न्यायाधिकरण के फैसले का इंतजार हो रहा था। भारत के इस दल में 7 महिलाएं भी शामिल थी। उड़ान को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलने के कारण वे रात दो बजे तक टर्मिनल के अंदर ही रहे। इसके बाद उड़ान रद्द होने की घोषणा की गई और बताया गया कि उस रात कोई वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था नहीं की जाएगी। जैसे ही टीम हवाई अड्डे से बाहर निकली, उनकी परेशानी बढ़ गई।

देश के सबसे प्रतिष्ठित कम्पाउंड पुरुष तीरंदाज वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ''बिना खिड़की वाली स्थानीय बस'' में भर दिया गया और लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक अस्थायी लॉज में ले जाया गया, जो एक 'धर्मशाला' जैसा था। इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि जिस स्थान पर टीम को ले जाया गया था, वह 'एक उचित होटल भी नहीं था', जिसमे महिलाओं के लिए एक कमरे में छह बिस्तरों वाला एक कमरा था और उसमें केवल एक शौचालय था जो बहुत गंदा था।

उन्होंने बताया, 'गेस्ट हाउस के नाम पर हमें जिस धर्मशाला में ठहराया गया उसकी स्थिति बेहद खराब थी। एक कमरे में छह बिस्तर लगाए गए थे और जो शौचालय था उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई स्नान कर सकता था।' अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने के उनके प्रयास भी सफल नहीं हो सके।

वर्मा ने कहा, 'अगर हमें पता भी होता कि हमें सुबह 11 बजे तक टिकट मिल जाएगा, तो भी हम हवाई अड्डे पर ही रुक जाते। क्योंकि उन्होंने (एयरलाइन ने) कुछ भी पुष्टि नहीं की थी।' अगली

सुबह सात बजे दल हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उन्हें और अधिक देरी का सामना करना पड़ा। कई तीरंदाज हैदराबाद और विजयवाड़ा जाने वाली अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए, जिसके कारण उन्हें महंगी बुकिंग करानी पड़ी।

वर्मा ने कठिन परिस्थिति में राष्ट्रीय टीम का समर्थन न करने के लिए एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, 'आपका विमान खराब हो गया और आपको पता है कि बाहर दंगे हो रहे हैं तो उन्होंने हमें स्थानीय बस में कैसे बिठाया। अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता।'

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान : विवादित पीटीआई नेता मूनिस के खिलाफ मामला बंद

इस्लामाबाद, एजेंसी। इंटरपोल ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी व विवादित पीटीआई नेता मूनिस इलाही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के पाकिस्तान के अनुरोध से संबंधित मामला बंद कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व संघीय मंत्री को पकड़ने के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी थी। लगभग तीन साल पहले इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद मुनिस स्पेन चले गए थे।

चिली में कम्युनिस्ट बनाम धुर दक्षिणपंथ के बीच मुकाबला

सैंटियागो, एजेंसी। चिलीवासियों ने रविवार को नए राष्ट्रपति व संसद के लिए मतदान किया। इसमें कम्युनिस्ट बनाम धुर दक्षिणपंथ के बीच मुकाबला है। यह दक्षिण अमेरिकी देश में राष्ट्रपति चुनाव के संभावित दो चरणों में से पहला चरण है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कोई भी उम्मीदवार 14 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से बचने के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत मतों की सीमा को पार नहीं कर पाया है।

पाकिस्तान में एक लाख से ज्यादा अफगान गिरफ्तार : संयुक्त राष्ट्र

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने इस साल अब तक एक लाख से अधिक अफगानियों को गिरफ्तार किया है। डॉन ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बलूचिस्तान में चगाई व क्वेटा और पंजाब में अटक देश भर में शीर्ष तीन जिले हैं, जहां इस साल सबसे अधिक अफगान नागरिक कार्ड एसीसी धारक अफगान नागरिकों को दस महीने से अधिक समय तक गिरफ्तार रखा गया।

फिलीपीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन

मनीला, एजेंसी। फिलीपीन की राजधानी मनीला में रविवार को करीब 27 हजार से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी रिजाल पार्क में इकट्ठा हुए थे। उनके हाथों में सफेद कपड़ों पर भ्रष्टाचार खत्म करो जैसे संदेश वाले पोस्टर थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। लोगों ने पुलिस पर पत्थर, बोतलें व फायर बम फेंके। 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इग्लेसिया नी क्रिस्टो नामक धार्मिक संस्था की ओर से आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शन में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में हुए करोड़ों डॉलर के भ्रष्टाचार को लेकर जवाबदेही की मांग की गई। प्रदर्शनकारी ने दोषियों को जेल भेजने और अपने पैसे लौटाने की मांग की। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जुलाई में इस घोटाले का खुलासा किया और एक जांच आयोग गठित किया। मार्कोस जूनियर ने कहा कि इस घोटाले की जांच में कोई नहीं बचेगा। घोटाले के खुलासे के बाद मार्कोस के चचेरे भाई सीनेट अध्यक्ष फ्रांसिस एस्कुडेरो व हाउस स्पीकर मार्टिन रोमुअल्डेज इस्तीफा दे चुके हैं।

सीरिया के स्वेदा में सांप्रदायिक हिंसा पर सुरक्षा बलों और सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी

दमिश्क, एजेंसी। सीरिया के दक्षिणी प्रांत स्वीदा में जुलाई में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के सिलसिले में सीरिया के सुरक्षा और सैन्य सेवाओं के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जांचकर्ताओं ने रविवार को यह जानकारी दी। स्वीदा में हिंसा की जांच कर रही एक सीरियाई समिति के प्रमुख ने राजधानी दमिश्क में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रगति पर चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने मृतकों की संख्या जारी नहीं की, यह कहते हुए कि यह अंतिम रिपोर्ट में बताई जाएगी, जो वर्ष के अंत तक आने की उम्मीद है। बता दें कि जुलाई के मध्य में द्रुज आध्यात्मिक नेता शेख हिकमत अल-हिजरी से जुड़े सशस्त्र समूहों ने स्थानीय बेडौइन कबीलों के साथ संघर्ष किया, जिसके बाद सरकारी बलों ने हस्तक्षेप किया, जिन्होंने प्रभावी रूप से बेडौइनों का पक्ष लिया। सैकड़ों नागरिक, जिनमें से अधिकांश द्रुज़ थे।

संविधान संशोधन के खिलाफ लाहौर में हड़ताल करेंगे वकील

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के लाहौर शहर में वकीलों ने उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ रविवार को हड़ताल की घोषणा की और न्यायाधीशों से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तीफा देने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बृहस्पतिवार को 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया, जिसमें रक्षा बलों के प्रमुख के एक नए पद और एक संवैधानिक न्यायालय के सृजन का प्रावधान है।

ड्रग ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक: 75 दिनों में 21वां हमला

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका ने शनिवार को पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर हवाई हमला किया, जिसमें तीन लोग मारे गए। अमेरिकी सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। यह सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना का ड्रग नावों पर किया गया 21वां हमला है। आंकड़ों के अनुसार, इन हमलों में अब तक 83 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के मुताबिक ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर हो रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन ने इन हमलों को अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए जरूरी कदम बताया। न्याय विभाग ने इन हमलों को सही ठहराया है और कहा गया है कि इन ऑपरेशनों में शामिल अमेरिकी सैनिकों को मुकदमा चलाने से छूट मिलेगी।

अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया : अमेरिकी दक्षिणी कमान ने रविवार को हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया ङ्ग पर जारी किया। वीडियो में विस्फोट दिख रहा है, जिससे नाव के परखच्चे उड़ गए। हमले के तुरंत बाद बोट में आग लग गई। मारे गए लोगों की राष्ट्रीयता या पहचान की जानकारी नहीं दी गई।

ट्रम्प बोले- ड्रग तस्करी करने वाले पर स्ट्राइक की : इससे पहले ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, 'मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे।' अमेरिका ने 10 नवंबर को भी पूर्वी प्रशांत महासागर में दो संदिग्ध नावों पर हवाई हमला किया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बताया कि ये नाव ड्रग्स लेकर जा रहे थे। इसमें 6 लोग मारे गए थए। हेगसेथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये नावें आतंकवादी संगठनों से जुड़ी थीं और कोकीन तस्करी कर रही थीं।

वेनेजुएला की ड्रग संगठन 'कार्टेल डे लोस सोल्स' आतंकवादी संगठन घोषित अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों, मानवाधिकार संगठनों और सहयोगी देशों ने इन हमलों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर हमले करने का कानूनी आधार साफ नहीं है। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि उसके पास पूर्ण कानूनी अधिकार हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को वेनेजुएला की ड्रग संगठन 'कार्टेल डे लोस सोल्स' को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया।

इससे अमेरिका में इस ग्रुप को किसी भी तरह की मदद देने वाला अपराधी माना जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यह संगठन 'ट्रेन डे अरागुआ' नामक अपराधी समूह के साथ मिलकर अमेरिका में नशीले पदार्थ भेजता है। ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस कार्टेल के नेता हैं, हालांकि मादुरो हमेशा इससे इनकार करते आए हैं। अमेरिकी अधिकारी मादुरो सरकार के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।

कैलिफोर्निया के ज्वेलरी शॉप से 1.4 करोड़ रुपए के गहने चोरी; दुकान मालिक ने बचाव में गोलीबारी की

कैलिफोर्निया, एजेंसी। कैलिफोर्निया में एक ज्वेलरी दुकान पर गुरुवार शाम मास्क पहने पांच लुटेरों ने धावा बोल दिया। उन्होंने करीब 1.4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली। हालांकि, दुकान मालिक के गोली चलाने के बाद सभी भाग निकले। घटना शाम 7 बजे के बाद हुई जब दुकान 'ओलिविया फाइन ज्वेलरी' से ग्राहक निकल चुके थे। काले कपड़े और मास्क पहने लुटेरे अचानक अंदर घुसे। कुछ के हाथ में कांच तोड़ने के औजार थे, जबकि एक दरवाजे पर पहरेदार बना रहा।

लुटेरे काउंटर पार कर ज्वेलरी निकालने लगे। तभी पीछे के कमरे से दुकान मालिक निकले और हैंडगन से 3-5 गोलियां चलाईं। लुटेरे एक-दूसरे पर गिरते हुए बाहर भागे। मालिक ने दरवाजे पर पहुंचकर और चेतावनी की गोलियां चलाईं। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन लुटेरे ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस को लुटेरों की गाड़ी शहर के बाहर मिली। जांच में पता चला कि डकैती से पहले वे इलाके में चक्कर लगा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। लुटेरों की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि वे मास्क और काले कपड़ों में थे।

हमें युद्धबंदियों के अदला-बदली शुरू किये जाने का भरोसा है: जेलेंस्की

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे पर अब कम ही बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब रूस और यूक्रेन मिलकर कुछ हद तक माहौल को हल्का बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि उनका देश रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली फिर शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिससे लगभग 1,200 यूक्रेनी कैदी वापस आ सकते हैं।

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'हमें ...युद्धबंदियों के अदला-बदली शुरू किये जाने का भरोसा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कई बैठकें एवं वार्ताएं हो रही हैं।'

गौरतलब है कि इस मुद्दे पर यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने एक दिन पहले वार्ता में प्रगति की घोषणा की थी। उमेरोव ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने कैदियों का आदान-प्रदान पुनः शुरू करने के लिए तुर्कीए और संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में बात की जा रही है। दोनों देश इस्तांबुल की मध्यस्थता में 1,200 यूक्रेनवासियों को हिरा करने के लिए कैदियों के आदान-प्रदान के

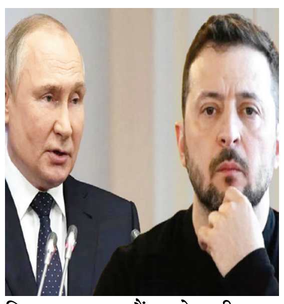

लिए सहमत हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से भले ही इस पर सहमति जता दी गई हो, लेकिन रूस की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें रूस और यूक्रेन दोनों ही इस्तांबुल समझौते 2022 के तहत कैदियों के आदान-प्रदान का सम्मान करते हैं। इसके तहत ही पिछले तीन सालों में दोनों देश हजारों सैनिकों का आदान-प्रदान कर चुके हैं। यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हवाई हमलों से बचने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहा है, जिसके कारण सर्दियों के शुरू होते ही समूचे यूक्रेन में बिजली गुल हो गई है। यूक्रेन की वायु सेना ने रविवार को बताया कि रूस ने रातभर में कुल 176 ड्रोन और एक मिसाइल दागी तथा यूक्रेनी सेना ने 139 ड्रोनों को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया। अग्रिम मोर्चे पर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

नेतन्याहू ने खाई कसम, कहा- अलग देश नहीं बन पाएगा फिलिस्तीन, अमेरिका को भी दो टूक

येरुशलम, एजेंसी। गाजा में युद्धविराम के बाद अब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर अपना प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। इसपर वोटिंग से पहले ही इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वह किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन नहीं करने वाले हैं। नेतन्याहू लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि फलस्तीनी राष्ट्र बनाने से हमास को लाभ होगा और इजराइल की सीमाओं पर अंततः हमास द्वारा संचालित एक और भी बड़ा राष्ट्र बनेगा। हालांकि, गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अमेरिका की कोशिशों के बीच नेतन्याहू को लचीलापन दिखाने के लिए भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

सुरक्षा परिषद द्वारा अमेरिका के प्रस्ताव पर मतदान किए जाने की संभावना है, जिसके तहत रूस, चीन और कुछ अरब देशों के विरोध के बावजूद गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की स्थापना की जाएगी। हमास और फलस्तीनी गुटों ने रविवार को अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ चेतावनी दी और इसे गाजा पर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय शासनादेश थोपने का प्रयास बताया जो इजराइल के प्रति पक्षपाती है और फलस्तीनियों को अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार से वंचित करता है। इन गुटों ने एक बयान में कहा कि इस बल में इजराइल शामिल नहीं होना चाहिए और यह सीधे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होना चाहिए।

बयान में अमेरिकी प्रस्ताव में गाजा को निरस्त्र करने के हर संदर्भ को खारिज कर दिया गया। नेतन्याहू ने रविवार को इस प्रस्ताव का उल्लेख किया जिसमें गाजा को सेना से मुक्त करने और हमास को निरस्त्र करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से कहा, ''यह या तो आसान तरीके से होगा, या कठिन तरीके से।'' नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के प्रति इजराइल के विरोध में ''जरा भी बदलाव नहीं आया है'' और उसे बाहरी या आंतरिक दबाव से बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, 'मुझे किसी की पुष्टि, किसी के ट्वीट या किसी के भाषण की जरूरत नहीं है।

कांगो में खदान ढहने से 80 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

ब्राज़ाविल, एजेंसी। दक्षिण-पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में शनिवार को एक खदान ढह गया। हादसे में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक अधिकारी ने रविवार को घटना की जानकारी दी। यह हादसा लुआलाबा प्रांत के मुलोंडो में कलांडो खदान में हुई।

प्रांत के गृह मंत्री रॉय कौम्बा मायोंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे के कारण खदान में जाने पर बैन लगा था। इसके बावजूद अवैध माइनिंग करने वाले खदान में जबरन खदान में घुस गए थे। डीआरसी की सरकारी एजेंसी एसएईएमएपीई की रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनास्थल पर सैनिकों की फायरिंग से माइनिंग करने वालो में

दहशत फैल गई और वे खदान के ऊपर पुल की ओर दौड़ पड़े, जिससे पुल ढह गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खदान के नीचे कई लोग खड़े दिखे। अचानक खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और उसके मलबे में कई लोग दब गए। कई लोग भागने के दौरान एक-दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे उनकी जान गई। बता दें कि डीआरसी दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक वाहनों और दूसरे प्रोजक्ट के लिए लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इस मध्य अफ्रीकी देश में उत्पादन का 80% हिस्सा चीनी कंपनियों के कंट्रोल में है। देश की खनन इंडस्ट्री लंबे समय से बाल मजदूरी, असुरक्षित परिस्थितियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के जूझ रही है।

इक्वाडोर का ड्रग गिरोह का सरगना स्पेन में पकड़ा गया : क्विटो, एजेंसी। इक्वाडोर के सबसे वांछित ड्रग तस्करों में से एक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कई साल पहले वो अपनी मौत का नाटक करके स्पेन भाग गया था। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने कहा कि विल्मर चावरिया, जिसे 'पिपो' के नाम से भी जाना जाता है, को स्पेनिश पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में स्पेन के शहर मलागा में पकड़ लिया गया। चावरिया को लॉस लोबोस का सरगना माना जाता है, जो लगभग 8,000 लड़ाकों वाला एक ड्रग तस्करी समूह है और जिसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। लॉस लोबोस का नाम इक्वाडोर में राजनीतिक हत्याओं से जुड़ा रहा है और उस पर मैक्सिको के जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के साथ मिलकर काम करने का भी आरोप है।

16 साल तक रचा खुद की मौत का नाटक, आखिरकार पकड़ा गया बुजुर्ग यौन अपराधी

न्यूयार्क, एजेंसी। अमेरिका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह पुलिस ने एक ऐसे यौन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसे वह पिछले 16 साल से मरा हुआ मान रही थी। आरोपी ने अपनी मौत का झूठा नाटक इतनी संजीदगी के साथ रचा था कि उसे स्वयं भी इस बात का भरोसा था कि पकड़े जाने से पहले ही वह मर जाएगा। स्थानीय पुलिस के मुताबिक फ्लोरिडा के इस शातिर अपराधी को इसी हफ्ते इंडियाना से गिरफ्तार किया गया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में अपनी मौत की झूठी कहानी रचने के बाद से फरार आरोपी गैरी बेन हार्वर्ड को यूएस

मार्शल्स ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के समय पर भी वह कह रहा था कि उसे उम्मीद थी गिरफ्तार होने के पहले वह मच चुका होगा।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गैरी नामक इस बुजुर्ग को 2007 में पिनेलेस काउंडी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने समेत 22 मामलों में दोषी पाया गया था। इसके बाद इसे आजीवन यौन अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि, 2010 में सभी लोगों को धोखा देते हुए गैरी फ्लारिडा से भागकर इंडियाना चला गया। अधिकारियों के मुताबिक उसने साजिश के तहत केंटकी की एक लेक में अपनी किराए की कार को ऐसी हालत में पार्क किया, जिसमें इस बात का पता चले कि उसने आत्महत्या कर ली है।

इस घटनाक्रम का पता पुलिस को तब चला जब गैरी ने 2011 में खुद को यौन अपराधी के रूप में रजिस्टर नहीं कराया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद यह मामला आया गया हो गया। पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि गैरी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि हाल ही में पुलिस को जानकारी मिली की गैरी जिंदा है। इसके बाद अदालत ने एक बार फिर से आदेश जारी करके कहा कि गैरी को फ्लोरिडा लाया जाए, जिससे वह अपने अपराधों का सामना कर पाए। टाइम्स के मुताबिक इसके बाद पुलिस कर्मियों ने जानकारी निकाली कि इंडियाना में गैरी के काफी जान पहचान वाले रहते हैं। इसके बाद मार्शल्स ने इंडियाना में गश्त बढ़ा दी और अंत में गैरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में उसे बैंडरबर्ग काउंटी जेल में भेजा गया है।

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ममदानी जल्द मुलाकात कर सकते हैं ट्रंप

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि वे न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने कहा कि वे 'कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे', राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान दोनों नेताओं के बीच चल रही सियासी बयानबाजी के बीच आया है।

ममदानी को देश से निकालने की ट्रंप ने की थी बात : ट्रंप पिछले कई महीनों से ममदानी पर तीखे हमले कर रहे थे। वे उन्हें गलत तरीके से 'कम्युनिस्ट' बताते रहे और दावा करते रहे कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ममदानी, जो युगांडा में जन्मे और बाद में अमेरिकी नागरिक बने, को देश से निकालने और शहर से संघीय फंडिंग रोकने की धमकी भी दी थी। ट्रंप के कठोर प्रवासी-विरोधी रुख के खिलाफ ममदानी का अभियान लेकिन न्यूयॉर्क की राजनीति ने अलग कहानी लिखी। 34 वर्षीय जोहरान ममदानी, जो कभी अपेक्षाकृत अंजान राज्य विधायक थे, सोशल मीडिया के सितारे बने और ट्रंप की नीतियों के मुखर विरोधी चेहरों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने प्रगतिशील नीतियों और ट्रंप के कठोर प्रवासी-विरोधी रुख के खिलाफ अभियान चलाया। मेयर चुनाव में उन्होंने पूर्व राज्यपाल एंड्रयू कुओमो को करीब 9 प्रतिशत अंकों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। अपनी जीत के भाषण में जोहरान ममदानी ने कहा

था कि न्यूयॉर्क देश को दिखाएगा कि ट्रंप की नीतियों का मुकाबला कैसे किया जाता है। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने यह भी कहा कि वे शहर के हित के लिए किसी से भी काम करने को तैयार हैं, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हों।

दोनों के बीच पिघल रही जमी बर्फ : जोहरान ममदानी की टीम ने रविवार को ट्रंप की टिप्पणी पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन यह दोहराया कि नवनिर्वाचित मेयर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे व्हाइट हाउस से संपर्क करेंगे, क्योंकि 'यह संबंध शहर की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।' ट्रंप ने भी रविवार को इसी सोच को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, 'न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहते हैं। हम कुछ न कुछ कर लेंगे।'

अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई- लेविट : व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बाद में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ममदानी की बात कर रहे थे। अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा, 'हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ अच्छा हो।

रूस से व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का कानून ला रही ट्रंप सरकार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन जल्द ही एक नया कानून बनाने जा रहा है, जिसके तहत रूस से व्यापार करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे समर्थन दे दिया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उनकी पार्टी एक विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत रूस से व्यापार करना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा।

विधेयक को लेकर ट्रंप क्या बोले

ट्रंप ने कहा कि 'रूस के व्यापारिक साझेदार देश यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देश। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसा विधेयक लाने जा रही है, जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर काफी कड़े प्रतिबंधों का प्रावधान है।'

भारत के लिए हो सकती है परेशानी : रूस से व्यापार करने वाले देशों में भारत और चीन शामिल हैं। ऐसे में अमेरिका के इस नए कानून से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। अमेरिका का मानना है कि रूस के यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने में भारत और चीन का प्रमुख योगदान है। नए कानून के तहत भारत और चीन के अलावा ईरान की भी परेशानी बढ़ सकती है।

भारत-रूस में बढ़ रहा द्विपक्षीय व्यापार : एक तरफ अमेरिका रूस से व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। साल 2030 तक दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। भारत और रूस के बीच इंडिया-यूरेशियन इकॉनोमिक यूनियन मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर अमेरिका का यह विधेयक पारित हो जाता है, तो ट्रंप उन देशों से आयात पर 500 प्रतिशत तक शुल्क लगा सकेंगे जो रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदते हैं।

पाकिस्तान: सिंध में अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 7 की मौत : लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अवैध पटाखा फैकटरी में विस्फोट हो गया। इसमें कम से कम सात लोग मारे गए और कई घायल हो गए। बचाव अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद शहर के लतीफाबाद इलाके में शनिवार रात एक गैरलाइसेंसी पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद शनिवार रात मकान का एक हिस्सा ढह गया। कुछ लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। बचाव दल के प्रवक्ता ने बताया कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। लतीफाबाद के सहायक आयुक्त सऊद लुंड ने घटनास्थल पर मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्टरी का मालिक असद जई फरार है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सऊदी अरब में तेलंगाना के तीर्थयात्रियों की मौत का मामला: भारत से जाएगा प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में रेजिडेंट कमिश्नर डॉ. शशांक गोयल की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और सऊदी अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हैदराबाद और दिल्ली में विशेष हेल्पलाइन शुरू कर दी गई हैं। हज हाउस में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल जल्द सऊदी अरब रवाना होगा।

बता दें कि सऊदी अरब के मदीना के निकट सोमवार को हुए भयावह सड़क हादसे ने तेलंगाना को झकझोर कर रख दिया है। हैदराबाद से उमराह करने गए 54 तीर्थयात्रियों से भरी बस की एक तेल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में45 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एकमात्र बचा व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल शोएब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मृतकों में 17 पुरुष, 18 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। हर शोक-संतप्त परिवार के दो सदस्यों को भी सऊदी भेजने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वे अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि यात्रियों का दल 9 नवंबर को जेद्दा रवाना हुआ था और 23 नवंबर को वापस लौटना था।

शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी शिनाख्त मुश्किल हो रही है। डीएनए जांच से पहचान कराने की तैयारी चल रही है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, ये मुबारक लोग पवित्र सफर पर थे।

हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटना है। शोक-संतप्त परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है।

तेलंगाना सरकार ने केंद्र से भी हरसंभव मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास पीड़ितों के शवों को जल्द भारत लाने और घायलों के इलाज में पूरा सहयोग कर रहा है। यह हादसा तेलंगाना के लिए इस साल की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया है।

कैंपस में करीब 70 फीसदी स्टाफ कश्मीरी था, गैर-कश्मीरी को रखा जाता था दूर

▶▶ डॉ. शाहीन ने खोले राज, अकाउंट में मिली रकम नहीं मिला रिकॉर्ड, रसीद या सबूत

नई दिल्ली

फरीदाबाद के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल मामले में आरोपी डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है, जिसमें कट्टरपंथ, गुप्त मीटिंग, और संदिग्ध फंडिंग शामिल है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कैंपस में कश्मीरी फैकल्टी का दायरा इतना मजबूत था कि उन्होंने एक खास ग्रुप बना लिया था, जिसमें बाहरी लोगों की कोई जगह नहीं थी।

मीडिया रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के मुताबिक डॉ. शाहीन ने बताया कि कैंपस में करीब 70 फीसदी स्टाफ कश्मीरी था, जिससे एक अलग भाषा और संस्कृति वाला माहौल बन गया। इस ग्रुप में गुप्त चर्चाएं होती थीं और गैर-कश्मीरी स्टाफ को जानबूझकर दूर रखा जाता था। यही नेटवर्क मुज़म्मिल और उमर जैसे मुख्य संदिग्धों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया, जहां से वह चुपचाप किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे।

इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के दो बड़े चेहरे उभरकर सामने आए हैं, जिन्होंने आतंक का काम आपस में बांट रखा था। इनमें से एक तो मुज़म्मिल हैं, जो कैंपस में वाहनों, मूवमेंट, पहुंच और स्टोरेज जैसे सभी लॉजिस्टिक को संभाल रहा था। वहीं दूसरा आतंकी उमर कट्टरपंथी विचारों को हवा देता था। वह तीखे बयान और धमकाने की शैली में निर्देश देता था। डॉ. शाहीन के मुताबिक उमर कई बार साफ कह चुका था कि एक बड़ा हमला होना है।

जांच में यह भी सामने आया है कि अल-फलाह कैंपस में एक जैसे कई बड़े ड्रम इधर-उधर ले जाए जा रहे थे। इन्हें 'सफाई कार्य' का हवाला देकर मूव किया जाता था, लेकिन शाहीन का दावा है कि यह गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था। ये सभी ड्रम एक लाल कार में ले जाए जाते थे। इस दौरान मुज़म्मिल और उमर की तुर्की यात्रा की चर्चाएं और पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट 'उक़ाशा' का नाम सामने आने से विदेशी हैंडलरों की भूमिका पर शक गहरा गया।

राजभवन में गोला-बारूद पर बंगाल में घमासान, गवर्नर के नेतृत्व में हुई तलाशी

▶▶ राज्यपाल का आदेश, टीएमसी सांसद के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करे

कोलकाता

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन परिसर में हथियार और गोला-बारूद जमा हैं। इन आरोपों के बाद, बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने सुरक्षाकर्मियों और खोजी कुत्तों की टीम के साथ राजभवन में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिक संगठनों के लोगों और पत्रकारों को साथ रखा। अभियान की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। राज्यपाल बोस के एक्शन पर टीएमसी सांसद बनर्जी ने फिर रिएक्शन देकर इस अभियान को बच्चों का खेल कहा। उसके बाद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राजभवन के अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल बोस ने कोलकाता पुलिस के अधिकारियों और केंद्रीय बलों, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की एक टीम का नेतृत्व किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंदर हथियार और गोला-बारूद जमा है या नहीं।

दरअसल तृणमूल सांसद ने दावा किया कि राज्यपाल को सबसे पहले अपराधियों को पनाह देना और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारने के लिए उन्हें हथियार और गोला-बारूद बांटना बंद करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक विवादास्पद बयान देकर, उन्हें पिछले हफ़्ते नई दिल्ली में हुए कार विस्फोट से जोड़ा, जिसमें 12 लोग मारे गए थे।

रोहिणी मामले पर लालू प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, कहा - घर का मामला, घर में ही सुलझेगा

पटना

रोहिणी आचार्य विवाद के बाद पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद ने साफ कहा कि यह हमारे घर का मामला है और इसे हम परिवार के भीतर ही सुलझा लेंगे।

लालू ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा कि हर परिवार में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वे स्वयं इस विवाद को निपटाने के लिए मौजूद हैं। बैठक में राबड़ी देवी, मीसा भारती, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी दौरान तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। लालू ने तेजस्वी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की और पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाया। लगभग चार घंटे चली इस बैठक में तेजस्वी ने पार्टी के जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों से अलग-अलग बातचीत की। बैठक में यह भी तय किया गया कि तेजस्वी एक बार फिर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में चुनाव परिणामों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। यह चर्चा भी हुई कि क्या परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।

पीएम मोदी से मुलाकात कर वित्त आयोग ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। आयोग द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी गई।

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्षीय अवधि (2026-2031) के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व की शुद्ध आय के बंटवारे के सिद्धांतों, राज्यों के बीच उनके संबंधित हिस्सों के आवंटन, राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि और शर्तों, आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण की व्यवस्था तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें करती है।

इससे पहले सोमवार को ही 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें भेंट की।

इसके बाद आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी रिपोर्ट की प्रति सौंपी। आधिकारिक बयान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 281 के प्रावधानों के तहत वित्त मंत्री द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के बाद इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

बिहार नहीं छोड़ूंगा, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरुक करने का काम करुंगा: पीके

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शर्मनाक हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरुक करने का काम जारी रखेंगे। बिहार चुनाव में हार का वह प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वह 20 नवंबर को अपने गांधी आश्रम में सामूहिक रूप से मौन उपवास करेंगे। उन्होंने राजनीति छोड़ने वाली बात से इनकार किया है। साथ ही कहा कि वह 6 महीने में संन्यास ले लेंगे अगर नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक काम कर लेगी। पटना में मंगलवार को प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी को बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने और हार मिलने की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि वह साढ़े 3 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प आए थे। ईमानदार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सकें। कुछ गलती हुई होगी, इसलिए जनता ने हम पर भरोसा नहीं किया। पीके ने कहा कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं लाए थे। स्वरोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए। सरकार ने यह भी वादा किया था कि 6 महीने में 2-2 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया था। पीके ने कहा कि अब नीतीश और बीजेपी की एनडीए सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह 2-2 लाख रुपये इन परिवारों को दें, ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके।

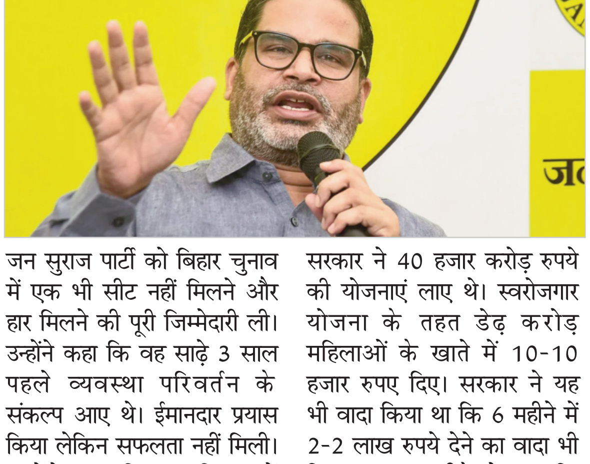

20 को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी, अमित शाह

जायसवाल बोले- कार्यक्रम में मतदाताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है

पटना

बिहार चुनाव 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के नेता इस कार्यक्रम को भव्य तरीक से आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसकी जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि समारोह में करीब 2 से 3 लाख लोग आएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। फिर 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अपार समर्थन एनडीए को दिया है, इसलिए इस कार्यक्रम में सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। करीब दो से तीन लाख लोग शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे।

जायसवाल ने कहा कि इस बार हम विकसित बिहार का सपना पूरा करने की शपथ लेंगे। जायसवाल ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर कहा कि अगर वह नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उन्हें अनुशासित तरीके से इसकी भूमिका निभानी चाहिए। एनडीए सरकार के विकसित बिहार के सपने में विपक्ष को अच्छे कामों में साथ देना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय क्षेत्र में अवैध रुप से मछली पकड़ रहे 79 बांग्लादेशी हिरासत में, बोट भी जब्त

नई दिल्ली भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में तीन बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को जब्त किया है। इन नावों पर सवार कुल 79 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई 15-16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी के दौरान की गई। आईसीजी के मुताबिक गश्ती दल ने इन विदेशी नौकाओं को भारतीय जलक्षेत्र में काफी अंदर तक अवैध रूप से संचालित होते पाया। जांच में किसी भी चालक दल के सदस्य के पास भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए जरुरी अनुमति पत्र नहीं मिला। नावों पर पकड़ी गई ताजा मछलियां और मछली पकड़ने के उपकरण इस अवैध गतिविधि की पुष्टि करते हैं। तटरक्षक बल ने तीनों नौकाओं को पूरी सुरक्षा के साथ फ्रेजरगंज तक एस्कॉर्ट किया, जहां उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मरीन पुलिस को सौंप दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तटरक्षक बल ने कहा कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र में निरंतर सतर्कता और कानून के सख्त अनुपालन को प्राथमिकता दी जा रही है।

आरक्षण से जुड़े मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ....हम चुनाव को ही रोक दें

नई दिल्ली आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चुनाव पर रोक तक लगाने की चेतावनी तक दे डाली है। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा की अनुमति नहीं मिल सकती है। खास बात है कि अदालत की तरफ से चेतावनी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच शुरु होने से एक दिन पहले आई है। सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि कुछ निकाय हैं, जहां ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 आरक्षण ने 50 प्रतिशत की सीमा पार कर दी है। इसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 मई को जारी आदेश का उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील सिंह ने कहा कि आदेश में चुनाव आयोग को जुलाई 2022 में आई बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के ओबीसी निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए थे। एडवोकेट सिंह और नरेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि 40 प्रतिशत से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर यह करीब 70 प्रतिशत है। बेंच ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार ही हो सकते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। शीर्ष अदालत का कहना है कि अब बांठिया आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं किया है, तब स्थानीय निकाय के चुनाव जुलाई 2010 से पहले लागू क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण के हिसाब से हो रहे है। महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की, लेकिन राज्य सरकार से कहा कि वह 50 प्रतिशत की सीमा से आगे न बढ़े। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तब हम चुनाव को ही रोक देने वाले है। इस अदालत की शक्तियों का इम्तिहान न लें। पीठ ने कहा, हमारा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था।

कर्नाटक में धर्म पूछकर लूट और मारपीट करने के लगे आरोप

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरु

बैंग्लुरु कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसका धर्म पूछने के बाद उसके साथ मारपीट की। एफआईआर के मुताबिक एक व्यक्ति रात करीब 11:15 बजे सेकंड क्रॉस डाउन के पास पैदल जा रहा था, तभी चार लोगों ने उसे रोका और पूछा कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूं। यह सुनने के बाद उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जेब से 50 हजार रुपए भी निकाल लिए। इसके बाद चाकू दिखाकर उसकी सोने की अंगूठी उतारने को कहा। पीड़ित ने बताया कि वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन हमलावरों ने पीछा किया। उसे पकड़ लिया और फिर पीटा। तभी एक बाइक सवार गुजरा, जिसे देखने के बाद हमलावर भाग गए। पीड़ित ने दो अस्पतालों में अपना इलाज कराया। वह डर के मारे दो दिन तक घर पर ही रहा। आखिरकार 17 नवंबर को उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवमोग्गा के विधायक एसएन चन्नबसप्पा पीड़ित के साथ दोड्डापेटे पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिवमोग्गा पुलिस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शहर में पुलिसिंग की कोई व्यवस्था बची है? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी नागरिक विवादों में दखल दे रहे हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा जैसे बुनियादी कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं।

साधु मॉब लिंचिंग के आरोपी काशीनाथ को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की हुई किरकिरी

मुंबई

पालघर साधु मॉब लिंचिंग के आरोपी रहे काशीनाथ चौधरी के भाजपा में शामिल होने और फिर 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता रद्द करने का मामला चर्चा में है।

दरअसल काशीनाथ चौधरी को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच पालघर जिला इकाई में भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। चौधरी पर वर्ष 2020 के चर्चित पालघर साधु मॉब लिंचिंग में शामिल होने का आरोप लगा था। चौधरी के भाजपा में शामिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद आगामी चुनावों में सियासी नुकसान से बचने के लिए भाजपा ने तुरंत दूरी बनाई।

प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने काशीनाथ चौधरी के प्रवेश पर रोक लगाकर फैसला निलंबित कर दिया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद भाजपा ने सफाई दी कि जांच रिकॉर्ड के अनुसार चौधरी किसी एफआईआर या आरोपपत्र में नामजद नहीं हैं, लेकिन मामले की संवेदनशीलता के कारण यह फैसला अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस और एनसीपी (शरद गुट) के नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा ने ही पहले चौधरी को साधु हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन अब उन्हें धूमधाम से पार्टी में शामिल कर रही है। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होकर कहा कि भाजपा ने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए, उसी को शामिल किया और मुख्यमंत्री प्रवेश को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे।